@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive www.kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

भाजपा में नेता मेधा और परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते हैं: जगत प्रकाश नड्डा

वर्ष-15, अंक-20 16-31 अक्टूबर, 2020 (पाक्षिक) ₹20

आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक 'अटल सुरंग'

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव हेतु भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हुई भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का एक दृश्य

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नवनियुक्त भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **'अटल सुरंग' राष्ट्र को समर्पित**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 अक्टूबर, 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 10 हजार फीट की ऊंचाई पर निर्मित 'अटल सुरंग' का उद्घाटन किया। मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ने वाली 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण...

श्रद्धांजलि

आमजन के हितचिंतक भैरोंसिंह शेखावत 19
प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक के. आर. मलकानी 19
केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान का निधन 20
भारत के पूर्व विदेश, वित्त व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह का निधन 27

लेख

निरंतर नेतृत्व का बीसवां वर्ष / जगत प्रकाश नड्डा 28
कांग्रेस को है बिचौलियों की चिंता, इसलिए किसानों को कर रही गुमराह / राकेश सिंह 29

मन की बात

जहां कहीं भी आत्मा है, वहीं एक कहानी है: नरेन्द्र मोदी 33

अन्य

भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ विरोध मार्च आयोजित 13
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्राकृतिक गैस मार्केटिंग सुधारों' को दी मंजूरी 16
'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना से जुड़े 28 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश 17
भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनेगा केंद्र: नरेन्द्र मोदी 21
कुम्हार सशक्तिकरण योजना देश की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक अभूतपूर्व पहल: अमित शाह 22
अभूतपूर्व श्रम कल्याण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देंगी श्रम संहिताएं: संतोष गंगवार 23
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 32

11 **भाजपा में नेता मेधा और परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते हैं: जगत प्रकाश नड्डा**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 08 अक्टूबर 2020 को वीडियो...

14 **भाजपा केन्द्रीय पदाधिकारियों की घोषणा**
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 सितंबर, 2020 को पार्टी के नए केन्द्रीय पदाधिकारियों और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं...

24 **संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थाओं में बदलाव आज समय की मांग है: नरेन्द्र मोदी**
संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर मैं भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की तरफ से...

30 **समग्र नदियों की स्वच्छता पर केंद्रित है यह मिशन: नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 सितम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'नमामि गंगे'...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

नरेन्द्र मोदी

देश में आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उसने ऐसे लोगों को परेशान कर दिया है, जिन्होंने हमेशा अपने राजनीतिक हितों के लिए काम किया। आज जब ऐसे लोगों द्वारा बनाए बिचौलियों और दलालों के तंत्र पर प्रहार हो रहा है, तो वे बौखला गए हैं। लेकिन देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है।

अमित शाह

संविधान निर्माताओं ने जिस 'कल्याण राज्य' की कल्पना की थी उसको चरितार्थ करने का काम श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। चाहे मुख्यमंत्री का पद हो या प्रधानमंत्री का, मोदी जी ने जन-कल्याण को सर्वोपरि रख अपना जीवन लोगों के कल्याण और देश के विकास के लिए समर्पित किया।

बी. एल. संतोष

ममता राज में देसी बम, केमिकल की बौछार; जो गुंडा+पुलिस राज के अलावा कुछ भी नहीं है। बंगाल भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके 'नबन्ना चलो' आंदोलन में यह सब झेलना पड़ा है। ममता आप हटेंगी जरूर, पर सबसे निर्दयी प्रशासक के खिताब के साथ।

facebook

जगत प्रकाश नड्डा

बिहार में विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। इस विकास को चलायमान रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। देश का नेतृत्व आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, अब बिहार का नेतृत्व नीतीश जी के हाथ में सुरक्षित हो। हम सबको मिलकर ये तय करना है कि बिहार में एनडीए की सरकार बने।

नितिन गडकरी

'अटल टनल' का आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। अटल जी के साथ आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना सपना पूरा हो गया है। इस टनल से मनाली और केलांग के बीच की दूरी 3-4 घंटे कम हो जाएगी और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए आवागमन में आसानी होगी, देश की सुरक्षा को भी इससे बल मिलेगा।

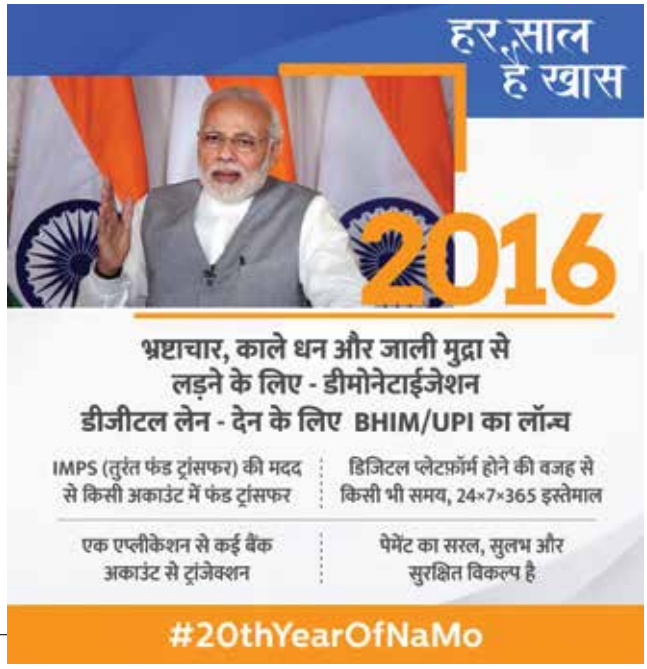

आशा एवं विश्वास के पर्याय नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्तूबर, 2020 को सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए 20वें वर्ष में प्रवेश कर लिया। पहली बार 7 अक्तूबर, 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसके बाद गुजरात ने विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए। परिणाम यह हुआ कि राज्य की जनता का अटूट एवं अपार विश्वास उन पर बना रहा। 7 अक्तूबर, 2001 से लोकसभा चुनाव 2014 में विशाल बहुमत प्राप्त करने तक श्री नरेन्द्र मोदी लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करते रहे तथा प्रदेश की जनता ने 2002, 2007 एवं 2012 के विधानसभा चुनावों में उन्हें बार-बार भारी बहुमत से विजयी बनाया। जहां एक ओर लोकसभा चुनाव 2014 में पूरे देश ने उन पर भारी भरोसा जताया, वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में उन्हें 2014 से भी बड़ा जनादेश देकर देश ने उनके नेतृत्व पर जबरदस्त विश्वास व्यक्त किया। इन वर्षों में देश ने उनके करिश्माई नेतृत्व, अद्भुत गतिशीलता, दूरदर्शी निर्णय, कठोर परिश्रम, निरंतर कार्य एवं अदम्य उत्साह को अनेक सफलताओं एवं अद्भुत उपलब्धियों में परिणत होते हुए देखा है।

एक ओर जहां श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सुशासन एवं विकास का एक चमकता हुआ मॉडल के रूप में उभरा, वहीं दूसरी ओर इसने देश के सामने भविष्योन्मुखी विकास एवं तीव्र प्रगति का एक नया चित्र प्रस्तुत किया। यह वह समय था जब कांग्रेसनीत संप्रग के कुशासन, 'पॉलिसी पैरेलिसिस', कमरतोड़ महंगाई, गिरती हुई विकास दर, आए दिन जनता के पैसों की लूट एवं भ्रष्टाचार से देश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात आशा की एक किरण बनकर उभरी। पूरे देश की जनता श्री नरेन्द्र मोदी को ऐसे नायक के रूप में देखने लगी, जो न केवल देश को इन विपरीत परिस्थितियों से उबार सकता था, बल्कि सुशासन एवं विकास के नए प्रतिमान गढ़ने की क्षमता रखता था। ऐसे परिदृश्य में जब लोकसभा चुनाव 2014 का परिणाम आया, तब देश की जनता ने तीन दशकों में पहली बार किसी राजनैतिक दल को पूर्ण बहुमत देकर देश में व्यापक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

> आज जब श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में बीसवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, पूरा देश उन्हें आशा एवं विश्वास के प्रतीक के रूप में देख रहा है जो राष्ट्र को नित नवीन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कृतसंकल्पित हैं।

भाजपानीत राजग को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत के परिणामस्वरूप देश में 'परफॉरमेंस', सुशासन एवं विकास की राजनीति का सूत्रपात हुआ। जैसाकि श्री नरेन्द्र मोदी ने शुरुआत में ही कहा था कि उनकी सरकार गरीब, वंचित, शोषित, महिला, अनु. जाति एवं जनजाति के लिए समर्पित रहेगी, ठीक उसी प्रकार पिछले छह वर्षों में 'अंत्योदय' के सिद्धांतों का पालन करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त शासन के माध्यम से मोदी सरकार ने देश की सेवा की है। गरीब, वंचित एवं शोषित के जीवन में अभिनव कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन आया है, जिससे न केवल उन्हें राहत मिली है एवं उनका सशक्तिकरण हुआ है बल्कि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक बहुमूल्य घटक बनकर उभरे हैं। पूरा देश उस सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को महसूस कर रहा है तथा वैश्विक मंचों पर भारत की उपलब्धियों को सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं संकल्पित नेतृत्व में देश ने न केवल दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए अपनी सीमाओं की सुरक्षा की है, बल्कि वैश्विक मंचों पर भारत का कद अभूतपूर्व ढंग से बढ़ा है।

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की अद्भुत उपलब्धियों को देश की जनता ने लोकसभा चुनाव 2019 में पूर्व से भी बड़ा जनादेश देकर अपना आशीर्वाद दिया है। देश, जिसने श्री नरेन्द्र मोदी के अनेक ऐतिहासिक निर्णयों से भारत में व्यापक परिवर्तन होते हुए देखा, आज 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों को प्राप्त करने को तत्पर है। आज जब श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में बीसवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, पूरा देश उन्हें आशा एवं विश्वास के प्रतीक के रूप में देख रहा है जो राष्ट्र को नित नवीन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। उनके करिश्माई, दूरदर्शी एवं सुदृढ़ नेतृत्व में देश अभूतपूर्व ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

'अटल सुरंग' राष्ट्र को समर्पित

9.02 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 अक्टूबर, 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 10 हजार फीट की ऊंचाई पर निर्मित 'अटल सुरंग' का उद्घाटन किया। मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ने वाली 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 'अटल सुरंग' हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में औसत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर अति-आधुनिक विशिष्टताओं के साथ बनाई गई है।

अटल सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी चार से पांच घंटे कम हो जाएगा। अटल सुरंग को अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ प्रतिदिन 3000 कारों और 1500 ट्रकों के यातायात घनत्व के लिए डिजाइन किया गया है।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने रोहतांग दर्रे के नीचे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस सुरंग का निर्माण कराने का निर्णय किया था और सुरंग के दक्षिणी पोर्टल पर संपर्क मार्ग की आधारशिला 26 मई, 2002 को रखी गई थी। मोदी सरकार ने दिसम्बर, 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में सुरंग का नाम 'अटल सुरंग' रखने का निर्णय किया था।

श्री मोदी ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को नजरअंदाज करने के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश ने लंबे समय तक एक ऐसा दौर भी देखा जब रक्षा हितों के साथ समझौता किया गया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा जरूरतों और रक्षा हितों का ध्यान रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमेशा से यहां अवसंरचनाओं को बेहतर बनाने की मांग उठती रही, लेकिन लंबे समय तक देश में सीमा से जुड़ी विकास की परियोजनाएं योजना के स्तर से बाहर ही नहीं निकल सकीं। उन्होंने कहा कि जो (परियोजनाएं) निकली भी वो या तो अटक गईं या फिर लटक गईं और भटक गईं।

अटल सुरंग का उदाहरण देते हुए श्री मोदी जी ने कहा कि साल 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सुरंग के

लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद इस काम को भी भुला दिया गया।

उन्होंने कहा कि हालत ये थी कि साल 2013-14 तक सुरंग के लिए सिर्फ 1300 मीटर का काम हो पाया था। विशेषज्ञ बताते हैं जिस रफ्तार से उस समय अटल सुरंग का काम हो रहा था, उसी रफ्तार से यदि काम होता तो यह 40 साल में जाकर शायद पूरा हो पाता।

बड़ी परियोजना के निर्माण में देरी से देश का भारी नुकसान होता है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसंरचना की इतनी बड़ी परियोजना के निर्माण में देरी से देश का हर तरह से नुकसान होता है। इससे लोगों को सुविधा मिलने में तो देरी होती ही है, इसका खामियाजा देश को आर्थिक स्तर पर भी उठाना पड़ता है।

एक नजर में 'अटल सुरंग'

- अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है। यह पूरे साल मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़कर रखगी है। इससे पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग-थलग रहती थी।
- यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर (10,000 फीट) की ऊंचाई पर अति-आधुनिक विनिर्देशों के साथ बनाई गई है।
- 'अटल सुरंग' मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है और दोनों स्थानों के बीच लगने वाले समय में भी लगभग 4 से 5 घंटे की बचत करती है।
- अटल सुरंग का दक्षिण पोर्टल (एसपी) मनाली से 25 किलोमीटर दूर 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि इसका उत्तर पोर्टल (एनपी) लाहौल घाटी में तेलिंग सिस्सू गांव के पास 3071 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
- यह घोड़े की नाल के आकार में 8 मीटर सड़क मार्ग के साथ सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली सुरंग है। इसकी ओवरहेड निकासी 5.525 मीटर है।
- यह 10.5 मीटर चौड़ी है और इसमें 3.6x2.25 मीटर फायर प्रूफ आपातकालीन निकास सुरंग भी है, जिसे मुख्य सुरंग में ही बनाया गया है।
- अटल सुरंग को अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ प्रतिदिन 3000 कारों और 1500 ट्रकों के यातायात घनत्व के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह सुरंग सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम, एससीएडीए नियंत्रित अग्निशमन, रोशनी और निगरानी प्रणाली सहित अति-आधुनिक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल प्रणाली से युक्त है।

उन्होंने कहा कि अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर पूरा हो पाती। आपकी आज जो उम्र है, उसमें 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिन आता, उनका सपना पूरा होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस वक्त के लिहाज से इसके निर्माण में तीन गुना से अधिक खर्च आया। श्री मोदी ने कहा कि अंदाजा लगाइए जब इसमें 20 साल और लग जाते तो क्या स्थिति होती।

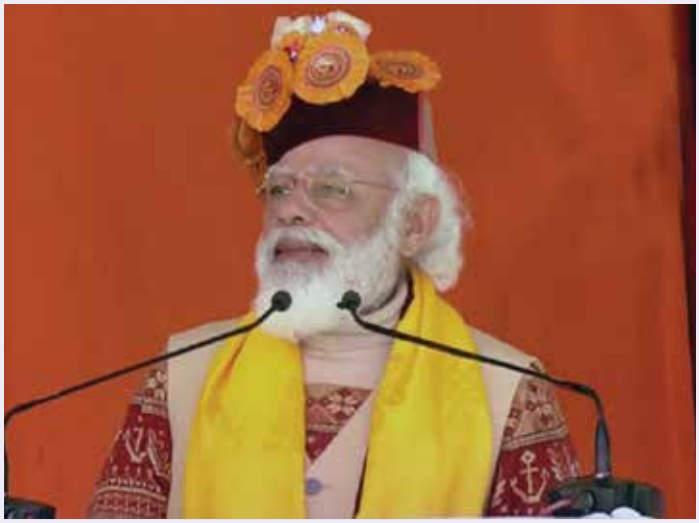

प्रधानमंत्री ने कहा कि संपर्क का देश के विकास से सीधा संबंध होता है और सीमा से जुड़े इलाकों में तो संपर्क देश की रक्षा जरूरतों से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर जिस गंभीरता की आवश्यकता थी, जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी, वैसी नहीं दिखाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अटल सुरंग की तरह ही अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया।

संपर्क का देश के विकास से सीधा संबंध होता है और सीमा से जुड़े इलाकों में तो संपर्क देश की रक्षा जरूरतों से जुड़ी होती है। इसे लेकर जिस गंभीरता की आवश्यकता थी, जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी, वैसी नहीं दिखाई दी। अटल सुरंग की तरह ही अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया।

उन्होंने सवाल किया कि लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के रूप में सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप 40-45 साल तक बंद रही। क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था। क्यों राजनीतिक इच्छाशक्ति नजर नहीं आई? मैं ऐसे दर्जनों परियोजनाएं बता सकता हूं, जो सामरिक दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से भले ही कितनी महत्वपूर्ण रही हों, लेकिन वर्षों तक नजरअंदाज की गईं।

इस क्रम में प्रधानमंत्री ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण असम के डिब्रूगढ़ शहर के पास बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबील पुल और बिहार में कोसी महासेतु का जिक्र किया और कहा कि 2014 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इन परियोजनाओं की गति में तेजी लाई गई और उन्हें पूरा किया गया।

उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से में संपर्क की बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का यही हाल रहा, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। इस दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किया गया है। सीमा क्षेत्र के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है।

इतने बड़े स्तर पर इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर इन क्षेत्रों में देश में पहले कभी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले छह सालों में सरकार के द्वारा किए गए कामों का बहुत बड़ा लाभ सामान्य जन के साथ फौजी भाई-बहनों को भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में भी देश की रक्षा से जुड़े सारे साजो-सामान दूसरे छोर पर आसानी से पहुंचाएं जा सके, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि देश की रक्षा जरूरतों, रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के फैसले साक्षी हैं कि जो वह कहती है, करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि देश हित से बड़ा, देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं। लेकिन देश ने लंबे समय तक वो दौर भी देखा है जब देश के रक्षा हितों के साथ समझौता किया गया।

उन्होंने कहा कि देश में ही आधुनिक अस्त्र-शस्त्र बने, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हथियार बनें, इसके लिए बड़े सुधार किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले छह सालों में देश की सेनाओं की मजबूती के लिए उठाए गए कदमों का उदाहरण देते हुए कहा कि देश की सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार साजो-सामान जुटाए जा रहे और उत्पादन भी किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास जनमानस का हिस्सा बन चुका है।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, थल सेना प्रमुख एम एम नरवणे और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ■

प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के सिस्सू गांव में आयोजित 'आभार समारोह' में हुए शामिल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति के सिस्सू गांव में आयोजित 'आभार समारोह' में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने उस समय को याद किया जब वे एक कार्यकर्ता के रूप में यहां पर काम करने के लिए रोहतांग के लम्बे रास्ते से आया-जाया करते थे तथा सर्दियों में रोहतांग दर्रे के बंद होने के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों को देखते थे।

श्री मोदी ने उन दिनों श्री ठाकुर सेन नेगी के साथ हुई अपनी बातचीत को भी याद किया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी इन परेशानियों से पूरी तरह वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने वर्ष 2000 में सुरंग के निर्माण की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 किलोमीटर सुरंग के माध्यम से लगभग 45-46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस सुरंग के परिवर्तनकारी प्रभाव से इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में बदलाव आने वाला है। यह सुरंग लाहौल-स्पीति और पांगी के लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इससे किसान, बागवानी और पशुपालन से जुड़े लोग, छात्र तथा व्यापारी भी लाभान्वित होंगे।

श्री मोदी ने कहा कि यह सुरंग इस क्षेत्र की कृषि उपज को बर्बाद होने से रोकेगी, क्योंकि इससे ये उपज तेजी से बाजारों तक पहुंच सकेंगी। इससे इस क्षेत्र के चन्द्रमुखी आलू को नये बाजार और नये खरीदार उपलब्ध होंगे। इस सुरंग से लाहौल-स्पीति में उगने वाले हर्बल औषधीय पौधों और मसालों की पहुंच और इस क्षेत्र की विश्वस्तर पर पहचान बनेगी। इसके अलावा यह सुरंग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बाहर निकलने वाले परिवारों को जरूरतों को पूरा करेगी।

पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा

प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र की जबर्दस्त पर्यटन संभावनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि देवदर्शन और बुद्ध दर्शन के संगम के रूप में लाहौल-स्पीति में अब नया आयाम जुड़ने वाला है। अब स्पीति घाटी में स्थित ताबो मठ तक पहुंचने के लिए दुनियाभर के लोगों को आसानी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरा क्षेत्र न केवल पूर्वी एशिया के बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बौद्धों के लिए भी एक बड़ा केन्द्र बन जाएगा। पर्यटन बढ़ने से युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अटल सुरंग सरकार की इस प्रतिबद्धता का सूचक है कि विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले लाहौल-स्पीति और ऐसे ही अनेक क्षेत्रों को उनके ही भरोसे छोड़ दिया जाता था, क्योंकि ये क्षेत्र कुछ लोगों की राजनीतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करते थे। लेकिन अब देश नयी सोच के साथ काम कर रहा है और नीतियां अब वोटों की संख्या के आधार पर तैयार नहीं की जाती हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है कि कोई भी भारतीय पीछे न छूटे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लाहौल-स्पीति इस परिवर्तन का एक बड़ा उदाहरण है। यह इससे भी स्पष्ट है कि यह उन जिलों में से है, जहां हर घर पाइप से जल की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है।

प्रधानमंत्री ने दलितों, आदिवासियों, पीड़ितों और वंचितों के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण, एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने, शौचालयों जैसी सुविधाओं का निर्माण, आयुष्मान भारत योजना के तहत कराने के लिए सरकार के प्रयासों को भी सूचीबद्ध किया। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ सतर्क रहें।

प्रधानमंत्री ने सोलंग में अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के सोलंग घाटी में अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पहले उन्होंने रोहतांग स्थित दुनिया के सबसे लम्बे अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया और हिमाचल प्रदेश के सिस्सू में आभार समारोह में भाग लिया।

साथ ही, प्रधानमंत्री ने हमीरपुर में 66 मेगावाट के धौलासिध जलविद्युत परियोजना के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे न केवल बिजली मिलेगी, बल्कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, विशेष रूप से ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों, बिजली परियोजनाओं, रेल कनेक्टिविटी और वायु कनेक्टिविटी के सरकार के प्रयासों में हिमाचल प्रदेश एक महत्वपूर्ण हितधारक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कीरतपुर-कुल्लू-मनाली रोड कॉरिडोर, जीरकपुर-परवाणू-सोलन-कैथलीघाट रोड कॉरिडोर, नांगल बांध-तलवाड़ा रेल मार्ग, भानुपाली-बिलासपुर रेल मार्ग में काम तेज गति से चल रहा है और इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रयास जारी हैं, ताकि हिमाचल के लोगों के इन सेवाओं का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लोगों के जीवन को आरामदायक बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ■

अटलजी का ड्रीम प्रोजेक्ट था 'अटल सुरंग': जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 3 अक्टूबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। 2014 के बाद से इस परियोजना को तेजी से निष्पादित करने और राज्य के लोगों की दशकों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। समुद्र तल से करीब तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर बनी लगभग 9.02 किलोमीटर लंबी 'अटल सुरंग' दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जो वर्ष भर देश को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। पहले घाटी करीब छह महीने तक भारी बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कटी रहती थी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि लगभग 3,300 करोड़ रुपए की कीमत से बनी अटल सुरंग देश की रक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2019 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में सुरंग का नाम 'अटल सुरंग' रखने का निर्णय किया था। इस सुरंग से मनाली से केलांग की दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी और अब मात्र महज डेढ़ घंटे में तय की जा सकेगी। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी भी अब 46 किलोमीटर कम हो गई है।

श्रद्धेय अटल बिहारी जी से मनाली में हुई एक मुलाक़ात का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस सुरंग की नींव श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में रखी थी। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल जी ने इस सुरंग के शिलान्यास के समय कहा था कि ये पत्थर हिमाचल प्रदेश के विकास की नींव का पत्थर है।

श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा के केंद्र की सत्ता से हटने के बाद श्रद्धेय अटल जी एक बार मनाली आये थे तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सुरंग का काम कैसा चल रहा है तो मैंने उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि सुरंग का काम काफी धीमा चल रहा है। तब इस पर श्रद्धेय अटलजी ने कहा कि सुरंग के शिलान्यास का पत्थर जो मैंने रखा है, यह मेरे दिल पर रखा गया है। तो मुझे इस बात की हार्दिक ख़ुशी है कि हिमाचल प्रदेश के विकास के जिस पत्थर को श्रद्धेय अटल जी ने रखा था, कांग्रेस ने जिस पत्थर को प्रदेश के विकास का रोड़ा बना दिया था, उसे हटा कर मां भारती के सच्चे सपूत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत की है।

उन्होंने कहा कि अटल सुरंग के उद्घाटन से आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने न केवल मनाली और लाहौल स्पीति के बीच की दूरियां ख़त्म की हैं, बल्कि उन्होंने हिमाचल में विकास की गति को तेज करने की राह में आई दूरियों और प्रदेश के आगे बढ़ने के नए विजन और उसके क्रियान्वयन के बीच की भी दूरियों को भी ख़त्म किया है। इससे हिमाचल प्रदेश की वादियों में विकास की एक नई सुबह हुई है। यह श्रद्धेय अटल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 'अटल सुरंग' माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिल के भी बहुत करीब है जिन्होंने हमारी रक्षा नीति के लिए इसके रणनीतिक महत्व की कल्पना की थी। उन्होंने हिमाचल में भाजपा की सेवा करने के दौरान राज्य के लिए इसके महत्व को महसूस किया था।

अटल सुरंग के उद्घाटन से आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने न केवल मनाली और लाहौल स्पीति के बीच की दूरियां ख़त्म की हैं, बल्कि उन्होंने हिमाचल में विकास की गति को तेज करने की राह में आई दूरियों और प्रदेश के आगे बढ़ने के नए विजन और उसके क्रियान्वयन के बीच की भी दूरियों को भी ख़त्म किया है। इससे हिमाचल प्रदेश की वादियों में विकास की एक नई सुबह हुई है। यह श्रद्धेय अटल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था।

श्री नड्डा ने कहा कि 'अटल सुरंग' भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ताकत देगी। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में यह विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता-जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विगत 6 वर्षों में पुरानी स्थिति को बदलने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों हिमालय क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, कारगिल, लेह-लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम में अनेक प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा चुके हैं। साथ ही दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। इस सुरंग के बन जाने से से मनाली और लाहौल स्फीति घाटी सालों भर एक-दूसरे से जुड़े रह सकेंगे। इससे पहले बर्फबारी की वजह से लाहौल स्फीति घाटी साल के 6 महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी।

श्री नड्डा ने कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग न केवल कनेक्टिविटी, बल्कि हमारी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेगी। विश्वस्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता-जागता उदाहरण 'अटल सुरंग' पूरे साल मनाली और लाहौल-स्पीति घाटी को जोड़े रखेगी। यह मनाली और केलांग के बीच की दूरी को भी काफी कम करेगी। ■

भाजपा में नेता मेधा और परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते हैं: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 08 अक्टूबर 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया और पार्टी पदाधिकारियों को आगे बढ़ने का मंत्र देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कांग्रेस-शिव सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कृषि सुधार कानूनों को लेकर भी कांग्रेस और विपक्ष को आड़े हाथों लिया।

श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियों में बहुत बड़ा अंतर है। बाकी पार्टियों के लिए परिवार ही पार्टी है जबकि हमारे लिए पार्टी ही परिवार है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। महाराष्ट्र भाजपा के भी सदस्यों की संख्या एक करोड़ से अधिक पहुंची है, इसके लिए प्रदेश भाजपा इकाई को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा संस्कृति, परंपरा, राष्ट्रवाद, अंत्योदय, एकात्म मानववाद और सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के समेकित दर्शन की रही है। देश की एकता, अखंडता और संस्कृति की रक्षा हमारी पहचान रही है। उन्होंने कहा कि हम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े हैं जिन्होंने हमें संपूर्णता में विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना सिखाया है। यदि अर्थनीति की बात करें तो हम समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण 'अंत्योदय' से 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' और उससे 'आत्मनिर्भर भारत' के अभियान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तेज गति से काम कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नीति के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और उनके नेतृत्व में हमारा हर कदम देश और महाराष्ट्र की जनता के लिए समर्पित है।

श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेता मेधा और परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते हैं, परिवार, जाति, धर्म या धन-बल के आधार पर नहीं। यह हमारी नैतिक व्यवस्था का परिणाम है। पार्टी के सोचने, समझने और मूल्यांकन का तरीका ऐसा है कि यहां आगे बढ़ने के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होती।

श्री नड्डा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए जिस तरह से समय पर साहसिक कदम उठाते हुए देश की 135 करोड़ जनता को एकजुट किया, वह अद्भुत है। इसने पूरे विश्व में जन-कल्याण की अवधारणा

को व्यापक स्वीकृति दिलाते हुए मानवता की सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। देश के 80 करोड़ गरीब लोगों के दो वक्त के भोजन हेतु मार्च से नवंबर तक के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई, यह अपने-आप में बड़ा कीर्तिमान है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, वोकल फॉर लोकल और गरीब कल्याण रोजगार योजना के माध्यम से जन-कल्याण के साथ-साथ देश के अर्थतंत्र की गति को भी तेज करने का व्यापक प्रयास किया।

श्री नड्डा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये का अलग से आवंटन किया गया। उन्होंने कहा कि कृषि के आधारभूत ढांचे के पारिस्थितिकी-तंत्र के विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। किसान को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिये पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराने, निर्बाध अंतर्राज्यीय व्यापार, कृषि उत्पादों की ई-ट्रेडिंग के लिये एक रूपरेखा बनाने की दिशा में कृषि सुधारों की तत्काल जरूरत थी। इसलिए, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि सुधारों को एक-एक करके आगे बढ़ाना शुरू किया। एक वृहत् परिचर्चा के पश्चात् लोकतांत्रिक तरीके से हाल ही में कृषि सुधार से संबंधित तीन विधेयक संसद से पारित हुए और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से अब ये क़ानून बन चुके हैं। इन विधेयकों ने किसानों को सशक्त करते हुए देश में 'वन नेशन, वन मार्केट' (One Nation, One Market) की अवधारणा को चरितार्थ किया है। पहले मंडियों में किसानों को मल्टिपल टैक्स देना पड़ता था, अब किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी मिली है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को कर-मुक्त और स्वावलंबन-युक्त बनाया है। किसानों को फसल बेचने की आजादी देने की अनुशंसा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, शरद पवार जी और शरद जोशी कमिटी ने भी की थी। तमाम अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी वकालत की थी, लेकिन यदि इन कृषि सिफारिशों को अमलीजामा पहनाने का प्रयास सार्थक तरीके से यदि किसी ने किया है तो वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ही हैं। शरद पवार जी कृषि सुधारों की बात करें तो बहुत अच्छा लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इसे इम्प्लीमेंट कर दें तो यह खराब कैसे हो गया? शरद पवार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत की थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे किसान हितैषी बनाते हुए लागू कर दिया तो हम एंटी-फार्मर कैसे हो गए? चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह APMC एक्ट को बदल देगी, किसान के ट्रेड पर कोई टैक्स नहीं होगा और अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन, जब आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के हित में कृषि सुधारों को लागू कर दिया तो कांग्रेस पार्टी के नेता ट्रैक्टर पर सोफा लगा कर घूमने लग गए। ये लोग तो किसानों की जीविका ट्रैक्टर का भी निरादर कर रहे हैं? कोई जिससे अपनी जीविका चलाता है, क्या वह उसे जला सकता है, उसका निरादर कर सकता है? कोई हल को जलाता है क्या? ऐसा करने वाले न किसान हैं और न ही इनमें किसानों की आत्मा बसती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम हल का भी सम्मान करेंगे, ट्रैक्टर का भी सम्मान करेंगे और किसानों का भी सम्मान करेंगे। फसलों की एमएसपी, स्वायल हेल्थ कार्ड और किसान सम्मान निधि को देने का काम किसने किया? कांग्रेस की सरकारों को किसानों के हित में निर्णय लेने से किसने मना किया था? ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी थे जिन्होंने किसानों को उनका अधिकार दिया जिसकी स्वामीनाथन जी ने भी मुक्त कंठ से सराहना की थी।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि बजट को 12,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.36 लाख करोड़ रुपये करने का कार्य किया है। आर्थिक गति भी काफी तेज हुई है। पिछले एक वर्ष में धारा 370 के उन्मूलन, ट्रिपल तलाक के खात्मे, सीएए के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर भव्य राम मंदिर के निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह दिखाता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ यदि काम किया जाय तो कुछ भी असंभव नहीं है।

श्री नड्डा ने कहा कि लॉकडाउन के समय महाराष्ट्र की भाजपा इकाई ने भी 'सेवा ही संगठन' अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लिया। महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2.30 करोड़ से अधिक फ़ूड पैकेट्स, 42.5 लाख से अधिक राशन किट्स और लगभग 68 लाख फेस कवर का वितरण किया तो हजारों गांवों को सैनिटाइज भी किया। इसके अतिरिक्त राज्य से लगभग चार लाख लोगों ने पीएम केयर्स फंड में भी योगदान दिया।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की एक-एक इंच भूमि सुरक्षित है। दौलतबेग ओल्डी रोड वर्षों बाद जाकर पूरा हुआ। आज भारत का डिफेन्स सिस्टम मजबूत है और दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यह आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत और ताकतवर भारत के स्थापित होने की तस्वीर है। चीन के साथ लगी सीमा पर तेज गति से इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार पर काम हो रहा है। विगत छः वर्षों में चीन से लगी सीमा पर सड़क बनाने के काम में 32 फीसदी का इजाफा हुआ है। साथ ही, इन रास्तों पर 14,450 मीटर के ब्रिजेज बनाए गए हैं और इसके निर्माण में विगत छः वर्षों में इसमें 98% वृद्धि हुई है। चीन से लगी सीमा पर 380 किमी प्रति वर्ष की दर से पिछले तीन वर्ष में वर्ल्ड स्टैण्डर्ड सड़कें बनाई गई हैं। श्री नड्डा ने कहा कि देवेंद्र फड़णवीस जी के नेतृत्व में पांच वर्षों में महाराष्ट्र ने विकास की बड़ी यात्रा तय की। उनके पांच वर्षों के शासन में महाराष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में 17वें से तीसरे स्थान पर पहुंचा, स्वास्थ्य में छठे से तीसरे स्थान पर पहुंचा और कृषि में तीन गुना अधिक निवेश हुआ। आज हम सब महाराष्ट्र की बदहाल स्थिति से वाकिफ हैं। आज महाराष्ट्र में राज्य सरकार की ऐसी स्थिति है कि दायें को बाएं का पता नहीं चलता, बाएं तो दायें का पता नहीं चलता और हाथ को हाथ नहीं दिखता। महाराष्ट्र की राज्य सरकार को कौन चला रहा है, यह कहां से चल रही है, किसी को मालूम नहीं। हमने लॉकडाउन में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अनवरत मानवता की सेवा में लगे रहे, लेकिन राज्य की कांग्रेस-शिव सेना-एनसीपी की सरकार उदासीन रही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने श्री देवेंद्र फड़णवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश दिया था। जनादेश भी भाजपा के पक्ष में था लेकिन राजनीति में कभी-कभी धोखा हो जाता है। लेकिन मैं इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय कांग्रेस, शिव सेना और एनसीपी, तीनों पार्टियां सदा-सदा के लिए विपक्ष में रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जनता सेवा का अवसर देगी। महाराष्ट्र की जनता इस अवसर का इंतजार कर रही है। वास्तव में जनादेश के साथ धोखा देवेंद्र फड़णवीस जी या कमल के फूल से नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की जनता से हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ऐसी स्थिति नहीं है कि उस पर कुछ बोला जाय। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नीति के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और उनके नेतृत्व में हमारा हर कदम देश और महाराष्ट्र की जनता के लिए समर्पित है। ■

भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ विरोध मार्च आयोजित

पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है: रवि शंकर प्रसाद

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने 08 अक्टूबर 2020 को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया और तृणमूल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा और कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में आज पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध मार्च आयोजित किया गया। इन प्रदर्शनों में भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

श्री प्रसाद ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एक और तानाशाही रूप सामने आया है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे या तो किसी झूठे मामले में फंसा दिया जाता है या शासन एवं प्रशासन द्वारा तंग किया जाता है या फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि विगत कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में अब तक 115 पार्टी कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो चुकी है और इनमें से किसी एक मामले में भी राज्य पुलिस द्वारा कोई प्रामाणिक कार्रवाई नहीं की गई है। विगत 04 अक्टूबर को ही हमारे एक युवा नेता एवं पार्षद श्री मनीष शुक्ला की पुलिस थाने के सामने नृशंस हत्या कर दी गई, जबकि उन्होंने हत्या से पूर्व ही वीडियो बना इस बात की आशंका जताई थी कि उनकी हत्या की जा सकती है। पार्टी के खिलाफ इसी तरह के हिंसात्मक हमले और पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण विरोध मार्च का आयोजन किया था।

पश्चिम बंगाल में जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे या तो किसी झूठे मामले में फंसा दिया जाता है या शासन एवं प्रशासन द्वारा तंग किया जाता है या फिर उसकी हत्या कर दी जाती है।

श्री प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के शांतिपूर्ण विरोध मार्च पर पुलिस और तृणमूल सरकार द्वारा समर्थित अराजक तत्वों द्वारा इतना बर्बर हमला किया गया कि भाजपा के 1,500 से अधिक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 70 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजू बनर्जी को गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें खून की उल्टियां हो रही हैं। काफी गंभीर परिस्थिति में अपोलो अस्पताल में इमरजेंसी में उन्हें एडमिट कराया गया है। हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री अरविंद मेनन भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या के साथ भी धक्कामुक्की की गई। पार्टी के सांसद श्री सौमित्र खान की पत्नी और पार्टी की कार्यकर्ता श्रीमती सुजाता खान को भी गंभीर चोटें आई हैं। बहुत सारे पार्टी कार्यकर्ताओं के सर फट गए हैं और उनके सर में भारी चोटें आई हैं। उत्तर कोलकाता के भाजपा अध्यक्ष श्री शिवाजी सिंह राय को भी गंभीर चोटें आई हैं। विरोध मार्च में महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की ख़बरें हैं। कई क्षेत्रों से ख़बरें आई हैं कि प्रदर्शन के रास्ते में तृणमूल समर्थित अराजकतावादी गुंडों द्वारा पथराव किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जो वाटर कैनन चलाया है, उसमें बहुत ही खराब केमिकल मिलाने की भी आशंका है जिससे लोगों के स्वास्थ्य का नुकसान भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे विरोध प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा किये गए बर्बरतापूर्ण आचरण की कड़ी भर्त्सना करती है।

श्री प्रसाद ने कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि आपको लगता है कि पुलिसिया दमन और लाठी के सहारे आप भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को पश्चिम बंगाल में रोक लेंगे तो आप इसमें कभी भी सफल नहीं होने वाले। आपने लोक सभा चुनावों के समय भी भाजपा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमें राज्य से 18 सीटों का समर्थन राज्य की जनता ने दिया। पश्चिम बंगाल की जमीन से यह स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में जब भी विधान सभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग राज्य में बदलाव के लिए संकल्पित हैं। ■

भाजपा केन्द्रीय पदाधिकारियों की घोषणा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 सितंबर, 2020 को पार्टी के नए केन्द्रीय पदाधिकारियों और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की घोषणा की। श्री नड्डा ने 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन), 3 राष्ट्रीय सह-महामंत्री (संगठन), 13 राष्ट्रीय सचिव और 23 राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए। इनके अलावा पार्टी के विभिन्न मोर्चा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष		प्रदेश
1.	डॉ. रमन सिंह, विधायक	छत्तीसगढ़
2.	श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, विधायक	राजस्थान
3.	श्री राधा मोहन सिंह, सांसद	बिहार
4.	श्री बैजयंत जय पांडा	ओडिशा
5.	श्री रघुबर दास	झारखंड
6.	श्री मुकुल रॉय	पश्चिम बंगाल
7.	श्रीमती रेखा वर्मा, सांसद	उत्तर प्रदेश
8.	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, सांसद	झारखंड
9.	श्रीमती (डॉ.) भारती बेन शियाल, सांसद	गुजरात
10.	श्रीमती डी.के. अरुणा	तेलंगाना
11.	श्री एम. चौबा एओ	नागालैंड
12.	श्री अब्दुल्ला कुट्टी	केरल
राष्ट्रीय महामंत्री		
1.	श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद	राजस्थान
2.	श्री अरुण सिंह, सांसद	उत्तर प्रदेश
3.	श्री कैलाश विजयवर्गीय	मध्य प्रदेश
4.	श्री दुष्यंत कुमार गौतम, सांसद	दिल्ली
5.	श्रीमती डी. पुरून्देश्वरी	आन्ध्र प्रदेश
6.	श्री सी.टी. रवि, विधायक	कर्नाटक
7.	श्री तरुण चुग	पंजाब
8.	श्री दिलीप सैकिया, सांसद	असम
राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन)		
1.	श्री बी.एल. संतोष	दिल्ली
राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री		
1.	श्री वी. सतीश	मुम्बई
2.	श्री सौदान सिंह	रायपुर
3.	श्री शिवप्रकाश	लखनऊ
राष्ट्रीय मंत्री		
1.	श्री विनोद तावड़े	महाराष्ट्र
2.	श्री विनोद सोनकर, सांसद	उत्तर प्रदेश
3.	श्री विश्वेश्वर टूडू, सांसद	ओडिशा
4.	श्री सत्या कुमार	आन्ध्र प्रदेश
5.	श्री सुनील देवधर	महाराष्ट्र
6.	श्री अरविन्द मेनन	दिल्ली
7.	श्री हरीश द्विवेदी, सांसद	उत्तर प्रदेश

8.	श्रीमती पंकजा मुंडे	महाराष्ट्र
9.	श्री ओमप्रकाश ध्रुवे	मध्य प्रदेश
10.	श्री अनुपम हाजरा	पश्चिम बंगाल
11.	डॉ. नरेन्द्र सिंह	जम्मू-कश्मीर
12.	श्रीमती विजया राहटकर	महाराष्ट्र
13.	श्रीमती (डॉ.) अल्का गुर्जर	राजस्थान
कोषाध्यक्ष		
1.	श्री राजेश अग्रवाल	उत्तर प्रदेश
सह-कोषाध्यक्ष		
1.	श्री सुधीर गुप्ता, सांसद	मध्य प्रदेश
केन्द्रीय कार्यालय सचिव		
1.	श्री महेन्द्र पाण्डेय	उत्तराखंड
प्रभारी राष्ट्रीय आई.टी. व सोशल मीडिया		
1.	श्री अमित मालवीय	उत्तर प्रदेश
मोर्चो के राष्ट्रीय अध्यक्ष		
युवा मोर्चा		
1.	श्री तेजस्वी सूर्या, सांसद	कर्नाटक
ओ.बी.सी. मोर्चा		
1.	डॉ. के. लक्ष्मण	तेलंगाना
किसान मोर्चा		
1.	श्री राजकुमार चाहर, सांसद	उत्तर प्रदेश
अनुसूचित जाति मोर्चा		
1.	श्री लाल सिंह आर्य	मध्य प्रदेश
अनूसूचित जनजाति मोर्चा		
1.	श्री समीर ओरांव, सांसद	झारखंड
अल्पसंख्यक मोर्चा		
1.	श्री जमाल सिद्दिकी	महाराष्ट्र

राष्ट्रीय प्रवक्ता		
1.	श्री अनिल बलूनी, सांसद, मुख्य प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी	उत्तराखंड
2.	श्री संजय मयूख, विधान परिषद सदस्य, मीडिया सह-प्रभारी	बिहार
3.	डॉ. संबित पात्रा	ओडिशा
4.	डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, सांसद	उत्तर प्रदेश
5.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	बिहार
6.	श्री राजीव प्रताप रूडी, सांसद	बिहार
7.	श्री नलिन एस. कोहली	दिल्ली
8.	श्री राजीव चन्द्रशेखर, सांसद	कर्नाटक
9.	श्री गौरव भाटिया	उत्तर प्रदेश
10.	श्री सैय्यद ज़फर इस्लाम, सांसद	उत्तर प्रदेश
11.	श्री टॉम वडक्कन	केरल
12.	श्रीमती संजू वर्मा	मुम्बई
13.	श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	दिल्ली
14.	श्री इकबाल सिंह लालपुरा	पंजाब
15.	सरदार आर.पी. सिंह	दिल्ली
16.	श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद	राजस्थान
17.	श्रीमती अपराजिता सारंगी, सांसद	ओडिशा
18.	श्रीमती हिना गावित, सांसद	महाराष्ट्र
19.	श्री गुरूप्रकाश	बिहार
20.	श्री मम्होनलुमो किकोन, विधायक	नागालैंड
21.	सुश्री नुपुर शर्मा	दिल्ली
22.	श्री राजू बिष्ट, सांसद	पश्चिम बंगाल
23.	श्री के.के. शर्मा	दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्राकृतिक गैस मार्केटिंग सुधारों' को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 7 अक्टूबर को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'प्राकृतिक गैस मार्केटिंग (विपणन) सुधारों' को मंजूरी दे दी।

इस नीति का उद्देश्य पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, गैस की बिक्री की बोली प्रक्रिया में सम्बद्ध गैस उत्पादकों को भाग लेने की अनुमति देने और उत्पादन साझा करने के ठेकों में पहले से ही मूल्य निर्धारित करने की आजादी देने वाली कुछ क्षेत्र विकास योजनाओं को विपणन की आजादी देकर गैस उत्पादकों द्वारा बाजार में बेची जाने वाली गैस के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए मानक कार्य पद्धति निर्धारित करना है।

इस नीति का उद्देश्य ई-बोली के जरिये ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली बिक्री के लिए दिशा-निर्देश जारी कर बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए मानक कार्य पद्धति प्रदान करना है।

इस नीति ने खुली, पारदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक बोली को ध्यान में रखते हुए सम्बद्ध कम्पनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की इजाजत दी है। इससे गैस की मार्केटिंग सरल हो जाएगी और प्रतिस्पर्धा को अधिक बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यदि सम्बद्ध गैस उत्पादक ही इसमें भाग लेते हैं और कोई अन्य बोलीकर्ता नहीं होंगे तो दोबारा बोली लगानी होगी।

यह नीति क्षेत्र विकास योजनाओं (एफडीपी) को उन ब्लॉकों की मार्केटिंग की आजादी देगी, जहां उत्पादन साझा करने के ठेके पहले से ही मूल्य निर्धारित करने की आजादी प्रदान कर रहे हैं। ये सुधार पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों पर आधारित हैं। गैस क्षेत्र में ये सुधार और गहरे होंगे और निम्नलिखित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे:

- उत्पादन से जुड़ी नीतियों की सम्पूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली, प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे और मार्केटिंग को अधिक पारदर्शी बनाया गया है जिसमें कारोबार को सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- ये सुधार प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में निवेश को बढ़ावा देकर और आयात निर्भरता को कम करके आत्मनिर्भर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे।
- ये सुधार निवेश को प्रोत्साहित कर गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में एक और मील का पत्थर साबित होंगे।
- बढ़े हुए गैस उत्पादन का उपभोग पर्यावरण में सुधार में मदद करेगा।
- ये सुधार एमएसएमई सहित गैस उपभोग क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेंगे।
- घरेलू उत्पादन शहरी गैस वितरण और सम्बद्ध उद्योगों जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों में निवेश बढ़ाने में मदद करेगा।

केंद्र सरकार ने कारोबार को सुगम बनाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निवेश को आसान बनाने के लिए अपस्ट्रीम क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार हाथ में लिए हैं। ओपन एसरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) जो निवेशक चालित क्षेत्रफल नीलामी प्रक्रिया है, उसने देश में पर्याप्त क्षेत्रफल बढ़ाया है।

2010 और 2017 के बीच किसी ब्लॉक का आवंटन नहीं किया गया, जिससे घरेलू उत्पादन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता प्रभावित हुई। 2017 के बाद से 105 अन्वेषण ब्लॉकों के अंतर्गत 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र आवंटित किया गया है। इससे आने वाले समय में घरेलू उत्पादन की स्थिरता सुनिश्चित होगी। सरकार गैस क्षेत्र में अनेक सुधार लेकर आई है और इसके परिणामस्वरूप पूर्वी तट में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है।

2010 और 2017 के बीच किसी ब्लॉक का आवंटन नहीं किया गया, जिससे घरेलू उत्पादन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता प्रभावित हुई। 2017 के बाद से 105 अन्वेषण ब्लॉकों के अंतर्गत 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र आवंटित किया गया है। इससे आने वाले समय में घरेलू उत्पादन की स्थिरता सुनिश्चित होगी।

सरकार गैस क्षेत्र में अनेक सुधार लेकर आई है और इसके परिणामस्वरूप पूर्वी तट में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। पूर्वी तट से गैस उत्पादन देश की बढ़ी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान देगा।

फरवरी 2019 में सरकार ने अपस्ट्रीम क्षेत्र में बड़े सुधारों को लागू किया और अधिकतम उत्पादन पर ध्यान देकर मिसाल के तौर पर परिवर्तन किया। ओएएलपी राउंड्स के अंतर्गत क्षेत्रफल आवंटित किया जा रहा है जो केवल कैट II और कैट III बेसिन की कार्य योजना पर आधारित होगा।

घरेलू गैस उत्पादन में पूर्ण मार्केटिंग और मूल्य निर्धारित करने की आजादी है। 28 फरवरी 2019 के बाद मंजूर सभी अन्वेषण और क्षेत्र विकास योजनाओं को पूर्ण बाजार और मूल्य निर्धारित करने की आजादी है। ■

'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना से जुड़े 28 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश

दो और राज्यों, तमिलनाडु तथा अरुणाचल प्रदेश को 1 अक्टूबर को 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के तहत 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह के साथ जोड़ा गया है। इसके साथ ही, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत अब कुल 28 राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश एक-दूसरे के साथ निर्बाध रूप से जुड़ चुके हैं। योजना के अनुसार ही अब इन 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएस के लाभार्थी 1 अक्टूबर 2020 से अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से एक ही पैमाने और केंद्रीय निर्गम मूल्य पर सब्सिडी वाले खाद्यान प्राप्त कर सकते हैं।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के ज़रिये मिलने वाले लाभों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य सभी एनएफएसए लाभार्थियों को एक विकल्प प्रदान करना है। योजना से जुड़े राज्यों के लाभार्थी एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) यंत्र पर बायोमेट्रिक/आधार के प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके एनएफएसए के तहत अपने कोटे का अनाज ले सकते हैं।

यह सुविधा पहले से ही 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और लद्दाख में लागू है। शेष राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मार्च 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने का लक्ष्य रखा

गया है। इस प्रणाली के माध्यम से अस्थायी रोजगार इत्यादि की तलाश में अक्सर अपना निवास स्थान बदलते रहने वाले प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों को अब कहीं पर भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने कोटे का खाद्यान्न उठाने का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। लाभार्थी इन 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) यंत्र पर बायोमेट्रिक/आधार आधारित प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके खाद्यान्न ले सकते हैं। ■

'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के तहत 30 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गए

गरीब कल्याण रोजगार अभियान' (जीकेआरए) के तहत 30 सितम्बर तक लगभग 30 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गए एवं 27,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं। यह अभियान प्रवासी मजदूरों, जो छह राज्यों अर्थात बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांवों में लौटे हैं, को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में कदम उठा रहा है। 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' अब इन राज्यों के 116 जिलों में आजीविका अवसरों के साथ ग्रामीणों को सशक्त बना रहा है।

इस अभियान के तहत 1,14,344 जल संरक्षण संरचनाओं, 3,65,075 ग्रामीण घरों, 27,446 पशु अहातों, 19,527 कृषि तालाबों और 10,446 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों सहित बड़ी संख्या में संरचनाओं का निर्माण किया गया है। जिला खनिज निधियों के माध्यम से 6727 कार्य आरंभ किए गए हैं, 1,662 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराये गये हैं, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कुल 17,508 कार्य आरंभ किए गए हैं और अभियान के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से 54,455 प्रत्याशियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अभी तक अभियान की सफलता 12 मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के रूप में देखी जा सकती है जो प्रवासी मजदूरों एवं ग्रामीण समुदायों को लाभ की उच्चतर मात्रा उपलब्ध करा रही है।

जीकेआरए कोविड-19 महामारी के बाद अपने गावों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों तथा इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था। जिन लोगों ने वापस रहने का फैसला किया, उनके लिए रोजगारों तथा आजीविकाओं के लिए दीर्घकालिक पहल के लिए एक लंबी अवधि की कार्रवाई के लिए समुचित तैयारी कर ली गई है। ■

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने विभिन्न हथियारों और उपकरणों के अधिग्रहण के लिए 2,290 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ की अध्यक्षता में 28 सितम्बर को आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों के अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसकी अनुमानित लागत 2,290 करोड़ रुपये है। इनमें घरेलू उद्योग के साथ-साथ विदेशी विक्रेताओं से खरीद शामिल हैं।

भारत में निर्मित की खरीद (आईडीडीएम) श्रेणी के तहत डीएसी ने स्टेटिक एचएफ ट्रांस-रिसीवर सेट और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (एसएएडब्लू) की खरीद को मंजूरी दी है। एचएफ रेडियो सेट, सेना और वायु सेना की क्षेत्र स्थित इकाइयों के लिए निर्बाध संचार को सक्षम बनाएगा और लगभग 540 करोड़ रुपये की लागत से इन्हें खरीदा जायेगा। लगभग 970 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की खरीद की जायेगी, जिससे नौसेना और वायु सेना की मारक क्षमता में वृद्धि होगी।

इसके अलावा, सेना के अग्रिम पंक्ति की सैन्य इकाइयों को उपकरणों से लैस करने के लिए डीएसी ने लगभग 780 करोड़ रुपये की लागत से एसआईजी सौएर असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए भी मंजूरी दी है।

सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज आफ टॉरपीडो का सफलतापूर्वक किया गया परीक्षण

ओडिशा तट से दूर व्हीलर द्वीप से 5 अक्टूबर, 2020 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज आफ टॉरपीडो (एसएमएआरटी) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसमें रेंज और ऊंचाई तक मिसाइल की उड़ान, आगे शंकु के आकार के नकीले भाग का पृथक्करण, टारपीडो का अलग होना और वेग न्यूनीकरण तंत्र (वीआरएम) की तैनाती सहित सभी मिशन उद्देश्यों का पूरी तरह से पालन किया गया है।

समुद्र तट के अलावा ट्रैकिंग स्टेशन (रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम) और डाउन रेंज जहाजों सहित दूरमापी स्टेशनों ने सभी घटनाओं की निगरानी की। एसएमआरटीए, टॉरपीडो रेंज से परे एक मिसाइल पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता (एएसडब्ल्यू) ऑपरेशन के लिए हल्के एंटी-सबमरीन टॉरपीडो सिस्टम की एक मिसाइल असिस्टेड रिलीज है। यह प्रक्षेपण और प्रदर्शन पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण है।

डीआरडीएल, आरसीआई हैदराबाद, एडीआरडीई आगरा, एनएसटीएल विशाखापत्तनम सहित कई डीआरडीओ प्रयोगशालाओं ने एसएमएआरटी के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास किया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी।

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड्स की आपूर्ति के लिए भारतीय कंपनी के साथ किया 409 करोड़ रुपये का अनुबंध

रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को और प्रोत्साहन देते हुए रक्षा मंत्रालय (एमओडी) की खरीद इकाई ने 1 अक्टूबर को भारतीय सेना को 409 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 10,00,000 मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स की आपूर्ति के लिए मैसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड (ईईएल), (सोलर ग्रुप) नागपुर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये ग्रेनेड भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे विश्व युद्ध-2 विंटेज डिजाइन वाले हैंड ग्रेनेड की जगह लेंगे।

मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड को डीआरडीओ/टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरीज (टीबीआरएल) द्वारा डिजाइन किया गया है और मैसर्स ईईएल, नागपुर द्वारा बनाया जा रहा है। ये उत्कृष्ट डिजाइन वाले ग्रेनेड हैं, जिन्हें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह की लड़ाई में उपयोग किया जा सकता है। भारत सरकार के संरक्षण में सार्वजनिक-निजी साझेदारी का प्रदर्शन करने वाली अग्रणी परियोजना अत्याधुनिक गोला बारूद प्रौद्योगिकियों में 'आत्मनिर्भरता' को सक्षम बनाती है और इसकी सामग्री 100 प्रतिशत स्वदेशी है। ■

सितंबर महीने में कुल 95,480 करोड़ रुपये रहा जीएसटी राजस्व संग्रह

सितंबर, 2020 महीने में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 95,480 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 17,741 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 23,131 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 47,484 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 22,442 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 7,124 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 788 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से 21,260 करोड़ रुपये के सीजीएसटी और 16,997 करोड़ रुपये के एसजीएसटी का निपटारा किया। सितंबर, 2020 महीने में नियमित निपटारे के बाद केन्द्र और राज्य सरकारों ने सीजीएसटी के लिए कुल 39,001 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 40,128 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।

बीते साल समान महीने की तुलना में सितंबर, 2020 में जीएसटी राजस्व 4 प्रतिशत अधिक रहा। बीते साल समान महीने की तुलना में सितंबर, 2020 के दौरान आयातित वस्तुओं से राजस्व 102 प्रतिशत और घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व 105 प्रतिशत रहा।

आमजन के हितचिंतक भैरोंसिंह शेखावत

(23 अक्टूबर 1923 - 15 मई 2010)

श्री भैरोंसिंह शेखावत भारत के ग्यारहवें उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज पर लम्बे समय तक छाये रहे। राजस्थान की राजनीति में उनका गहरा प्रभाव था। श्री शेखावत 1952 में विधायक बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अनेक सफलताएं अर्जित करते हुए वे विपक्ष के नेता, फिर मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति बने। श्री शेखावत जनसंघ के प्रारंभिक काल से ही जुड़ गये और 'जनता पार्टी' तथा 'भाजपा' की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत का जन्म 23 अक्टूबर, 1923 को सीकर (राजस्थान) में हुआ। इनके पिता का नाम श्री देवी सिंह और माता श्रीमती बन्ने कंवर थीं। श्री शेखावत ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही प्राप्त की। हाईस्कूल करने के पश्चात् उन्होंने जयपुर के 'महाराजा कॉलेज' में प्रवेश लिया। उन्होंने पुलिस की नौकरी भी की, लेकिन उसमें मन नहीं रमा और त्यागपत्र देकर खेती करने लगे।

वर्ष 1952 में वे 10 रुपये उधार लेकर दाता रामगढ़ से चुनाव के लिए खड़े हुए। इस चुनाव में वे विजयी हुए। इस सफलता के बाद उनका राजनीतिक सफर लगातार चलता रहा। वे 10 बार विधायक, 1974 से 1977 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। अपने लम्बे राजनीतिक सफर में श्री शेखावत 1977 से 1980, 1990 से 1992 और 1993 से 1998 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और 2002 में भारत के उपराष्ट्रपति बने। श्री शेखावत का निधन 15 मई 2010 को हुआ।

आजीवन राष्ट्रहित में काम करने वाले जननेता शेखावत जी ग़रीबों के सच्चे सहायक थे। उन्होंने कहा कि मैं ग़रीबों और वंचित तबके के लिए काम करता रहूंगा, ताकि वे अपने मौलिक अधिकारों का गरिमापूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ■

प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक के. आर. मलकानी

(19 नवम्बर 1921 - 27 अक्टूबर 2003)

श्री केवलराम रतनमल मलकानी (के. आर. मलकानी) एक प्रखर चितंक, राजनेता, आदर्शवादी, सैद्धांतिक पत्रकार व कर्मयोगी थे। वे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं पांडिचेरी के राज्यपाल रहे। वह एक प्रखर विचारक एवं लेखक भी थे। मलकानी जी का जन्म 19 नवंबर, 1921 को हैदराबाद (सिन्ध) में हुआ था। युवाकाल में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए और 1941 से 2003 तक वे आजीवन संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक रहे। मलकानी जी भारतीय जनसंघ के जन्मकाल से ही उसके सिद्धान्तकार बन गए। उनके ही आग्रह पर पं. दीनदयाल उपाध्याय ने आर्गेनाइजर में साप्ताहिक 'पालिटिकल डायरी' लिखना प्रारंभ किया।

मलकानी जी निर्भीक व निःस्वार्थी थे। उनका जीवन बहुत सादा और कठिन था। 1971 में 'मदरलैंड' नामक दैनिक पत्र प्रारंभ हुआ। मदरलैंड के संपादन का जिम्मा व प्रबंधन मलकानी जी पर था। आपातकाल की घोषणा के बाद मलकानी जी गिरफ्तार कर लिए गए और पूरे उन्नीस महीने जेल काटकर आपातकाल समाप्त होने पर छोड़े गए। उनके जेल जीवन की कहानी उनकी कलम से 'मिडनाईट नॉक' नामक पुस्तक के रूप में सामने आयी। 'मदरलैंड' बंद होने के बाद मलकानी जी पुनः आर्गेनाइजर के संपादक पद पर वापस आये और 1982 में 62 वर्ष की आयु में आर्गेनाइजर के संपादक दायित्व से निवृत्त हुए। मलकानी जी ने भाजपा के मुखपत्र 'बीजेपी टुडे' का भी संपादन किया।

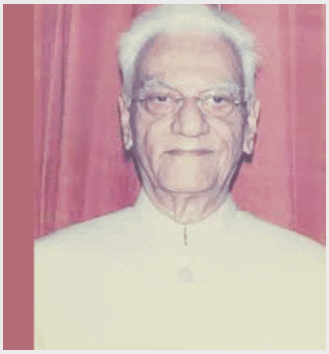

मलकानी जी भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय कार्यसमिति में आमंत्रित रहते थे। जब उन्हें उपाध्यक्ष पद सौंपा गया तब उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान के गैर-राजनीतिक चरित्र का आदर करते हुए उसके दायित्वों से मुक्ति ले ली और वे उपाध्यक्ष के नाते भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय में पूरे समय बैठने लगे। 1994 से 2000 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे, पर उनकी कलम कभी रुकी नहीं।

मलकानी जी आजन्म योद्धा रहे। संपादक के पत्र स्तंभ हो, या टेलीविजन पर बहस, हर जगह मलकानी जी का राष्ट्रवादी स्वर गूंजता रहा। वे जुलाई, 2002 में पांडिचेरी के उपराज्यपाल पद पर नियुक्त हुए। 27 अक्टूबर, 2003 को उन्होंने अंतिम सांस ली। मलकानी जी का जीवन आदर्शवादी, सिद्धान्तनिष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रकाशस्तंभ है और प्रेरणास्रोत है। ■

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान का निधन

लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता व भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री राम विलास पासवान का 8 अक्टूबर, 2020 को निधन हो गया। श्री पासवान वर्तमान केन्द्र सरकार में उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री पासवान के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि श्री पासवान के निधन से राष्ट्र ने एक प्रख्यात नेता, एक उत्कृष्ट सांसद और एक कुशल प्रशासक खो दिया है। ■

मैंने मूल्यवान सहयोगी खो दियाः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री पासवान के निधन पर दुःख जताया। सिलसिलेवार ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राम विलास पासवान जी का निधन एक व्यक्तिगत क्षति है। मैंने एक दोस्त, मूल्यवान सहयोगी और ऐसे व्यक्ति को खो दिया है, जो हर गरीब की गरिमापूर्ण जिंदगी की सुनिश्चित करने के लिए बेहद उत्सुक था।

उन्होंने कहा कि श्री राम विलास पासवान जी ने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से राजनीति में कदम रखा। एक युवा नेता के रूप में उन्होंने आपातकाल के दौरान अत्याचार और लोकतंत्र पर हमले का विरोध किया। वह एक उत्कृष्ट सांसद और मंत्री थे, जिन्होंने कई नीतिगत क्षेत्रों में स्थायी योगदान दिया।

श्री मोदी ने कहा कि साथ में काम करना, पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है। मंत्रिमंडल की बैठकों के दौरान उनके हस्तक्षेप ज्ञानवर्धक होते थे। राजनीतिक ज्ञान, राज्य-कौशल से लेकर शासन के मुद्दों तक वह प्रतिभाशाली थे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। ■

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे राम विलास पासवानः जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान के निधन पर दुःख व्यक्त किया। श्री नड्डा द्वारा जारी किया गया शोक संदेश निम्न हैः

केंद्रीय मंत्री, समाजवाद के प्रखर स्तंभ एवं लोकप्रिय जन-प्रतिनिधि श्री राम विलास पासवान जी के असामयिक निधन से दुःखी एवं स्तब्ध हूं। वे हमारे बीच नहीं रहे, यह दिल को बहुत दुःख देने वाली खबर है। वे ऐसे जननेता थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, शोषितों, वंचितों और पीड़ितों के उत्थान में समर्पित कर दिया था।

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री पासवान ने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एक लंबा सफ़र तय किया है। वे पहली बार 1969 में बिहार विधानसभा पहुंचे थे। वे 9 बार लोक सभा और दो बार राज्य सभा के सदस्य रहे। वे पिछले पांच दशक से भी ज्यादा वक्त से राजनीति में सक्रिय थे और देश के बड़े नेताओं में उनकी पहचान होती थी। उन्होंने देश के छः प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने उन्होंने श्रम कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संसदीय मामलों के मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कोयला एवं खदान मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, स्टील मंत्रालय से लेकर खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का काम बखूबी संभाला।

श्री पासवान बेहद सरल और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे। अपने स्वभाव से वे सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। मैंने उन्हें अपने युवा काल से ही देखा है। जब मैं पटना में विश्वविद्यालय का छात्र था, तब वे वहां अक्सर छात्रों से मिलने आया करते थे। वे सदैव एक फायरब्रांड नेता के रूप में प्रतिष्ठित रहे, जिन्होंने हमेशा गरीबों, पीड़ितों, वंचितों व समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। उनका निधन न केवल बिहार, बल्कि समग्र राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं है।

दुःख की इस घड़ी में मैं स्वयं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धेय श्री राम विलास पासवान के शोकाकुल परिवार एवं सहयोगियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही, भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को धैर्य और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ॐ शांति। ■

भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनेगा केंद्रः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अक्टूबर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर एक मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन, रेज़ (आरएआईएसई) 2020 का उद्घाटन किया। रेज़ 2020 विचारों के आदान-प्रदान और स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे अन्य क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेश और सशक्तिकरण के लिए एआई का उपयोग करने के लिए एक वैश्विक बैठक है।

प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजकों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी ने हमारे कार्य स्थलों में परिवर्तन और सम्पर्क में सुधार किया है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि सामाजिक जिम्मेदारी और एआई के बीच विलय से मानवीय सम्पर्क मज़बूत होगा। उन्होंने कहा कि मानव के साथ एआई का टीम वर्क पृथ्वी के लिए चमत्कार कर सकती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ज्ञान और शिक्षा में दुनिया का नेतृत्व किया है और अब भारत दुनिया को डिजिटल रूप से उत्कृष्ट और खुशहाल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने अनुभव किया है कि तकनीक पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार करने में किस तरह से मदद करती है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी विशिष्ट पहचान प्रणाली-आधार के साथ-साथ दुनिया की सबसे नवीन डिजिटल भुगतान प्रणाली-यूपीआई ने वित्तीय सेवाओं सहित डिजिटल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने और गरीबों तथा दबे कुचले लोगों के बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महामारी के दौरान यह जल्द से जल्द और सबसे कुशल तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाने में सक्षम हुआ है।

श्री मोदी ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक केंद्र बनने की कामना की। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में कई और भारतीय इस दिशा में काम करना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य के प्रति दृष्टिकोण- टीम वर्क, विश्वास, सहयोग, जिम्मेदारी और समावेश के मुख्य सिद्धांतों द्वारा संचालित है।

सामाजिक जिम्मेदारी और एआई के बीच विलय से मानवीय सम्पर्क मज़बूत होगा। साथ ही, मानव के साथ एआई का टीम वर्क पृथ्वी के लिए चमत्कार कर सकती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाया है। यह नीति शिक्षा के प्रमुख भाग के रूप में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा और कौशल पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि ई-पाठ्यक्रम को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में भी विकसित किया जाएगा। इस पूरे प्रयास से एआई प्लेटफार्मों की प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) क्षमताओं से लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 में शुरू किए गए 'युवाओं के लिये उत्तरदाई आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' कार्यक्रम के तहत, स्कूलों के 11,000 से अधिक छात्रों ने बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया। वे अब अपनी एआई परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम डिजिटल बुनियादी ढांचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक ई-शिक्षा इकाई बनाएगा। उन्होंने वर्चुअल लैब और अटल इन्नोवेशन मिशन की स्थापना जैसी उभरती तकनीकों के साथ तालमेल रखने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम समाज की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित होगा।

श्री मोदी ने उन क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया, जिसमें एआई ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। इनमें कृषि, अगली पीढ़ी के लिए शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण, शहरी मुद्दों और समस्याओं का समाधान करना है। शहरी समस्याओं में यातायात की समस्या को कम करना, सीवेज सिस्टम में सुधार और ऊर्जा ग्रिडों को बनाना, आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत बनाना जलवायु परिवर्तन शामिल हैं।

उन्होंने एआई का उपयोग करके भाषा की बाधाओं को मूल रूप से समाप्त करना और भाषाओं तथा बोलियों की विविधता को संरक्षित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने ज्ञान के प्रसार के लिए एआई का उपयोग करने का भी सुझाव दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई का उपयोग कैसे किया जाता है, यह विश्वास स्थापित करने के लिए एल्गोरिथम पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और इसे सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने गैर-सामाजिक तत्वों द्वारा एआई के दुरुपयोग के खिलाफ दुनिया की रक्षा करने का आग्रह किया। ■

कुम्हार सशक्तिकरण योजना देश की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक अभूतपूर्व पहलः अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 30 सितंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के 20 गांवों के 200 प्रशिक्षित परिवारों के कुम्हार को विद्युत चालित चाक वितरित किए। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि समाज के गरीब व वंचित वर्ग को सशक्त कर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पंडित दीनदयाल उपध्याय जी ने कहा था गरीबों के घर में दिए जलाने से और उन्हें रोजगारी देने से बड़ा काम कोई नहीं है। विद्युत चालित चाक के वितरण से अहमदाबाद जिले के प्रजापति समाज के 200 परिवारों को नई दिशा मिलने जा रही है।

श्री शाह ने कहा कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना देश की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक अभूतपूर्व पहल है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हार भाइयों-बहनों को प्रशिक्षित कर अन्य उपकरण भी वितरित किये हैं जिससे उनका काम सरल होगा और समय की बचत के साथ साथ उनके उत्पादन व आय में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर ज़ोर दिया है। आज पर्यावरण के प्रति लोगों में जागृति आ रही है, घरों में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बढ़ रहा है। लोग रोटी बनाने के लिए लोहे की जगह मिट्टी के तवे का उपयोग करने लगे हैं। लोगों ने फ्रीज के पानी की जगह मटके का पानी पीना शुरू किया है। श्री शाह ने यह भी कहा कि रेलवे स्टेशन और दूसरी जगह प्लास्टिक की चीजों का उपयोग बंद कर के कुल्हड़ और मिट्टी के दीए जैसी वस्तुएं पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिससे रोजगार को खूब बढ़ावा मिलेगा। कुछ दिनों में नवरात्रि भी आ रही है। उसके बाद शरद पूनम और दिवाली के त्योहार आएंगे, इसलिए दीयों और मिट्टी की अन्य वस्तुओं की खपत बढ़ेगी।

श्री शाह ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग से रेलवे के साथ प्रजापति समाज का टाई अप कराने की अपील की, ताकि वे एक संस्था बनाकर रेलवे को अपनी वस्तुएं बेच सकें। उन्होंने कहा कि गुजरात में सहकारी मॉडल मजबूत है। तालुका स्तर की सहकारी संस्था प्रजापति समाज से कुल्हड़ खरीदे इससे सामान बेचने के लिए बाहर जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

इससे पहले श्री अमित शाह ने 24 जुलाई को गांधीनगर ज़िले के बालवा गांव के 40 कुम्हार परिवारों को विद्युत चालित चाक वितरित किए थे। इस योजना के अंतर्गत अब तक गुजरात के 840 कुम्हार परिवारों को विद्युत चालित चाक दिये गए हैं, जिससे उन्हें उनके गृह स्थान पर ही रोजगार उपलब्ध हुआ है।

गांधीनगर और अहमदाबाद में बड़ी संख्या में कुम्हार परिवार रहते हैं जो अपनी परंपरागत चाक पर मिट्टी के बर्तन, दीये और गमले आदि बनाकर उन्हें राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बेचते हैं। ऐसे प्रशिक्षित कुम्हार परिवारों को विद्युत चालित चाक दिये जाने से उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ ही उनकी आय में वृद्धि भी हुई है। कुम्हार सशक्तिकरण योजना के फलस्वरूप उनकी आय 2,500-3,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 10,000 रुपये प्रतिमाह तक हो गई है।

भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 10 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही कुम्हार परिवारों को ब्लंजर मशीन तथा पग मिल भी वितरित किए जा रहे हैं, जिससे मिट्टी को मिलाने का काम आसान होगा और कम समय में ज्यादा मिट्टी तैयार की जा सकेगी। विद्युत चालित चाक पर कुम्हार चाक की गति को भी नियंत्रित कर सकेंगे जिससे काम करना सरल होगा तथा उत्पादन में वृद्धि होगी। ■

अभूतपूर्व श्रम कल्याण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देंगी श्रम संहिताएं: संतोष गंगवार

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार ने 3 अक्टूबर को कहा कि कृषि मंत्रालय का बजट पिछले 10 वित्त वर्ष में 11 गुणा बढ़कर 1.34 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2009-10 में 12,000 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि यह देश में किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को देश में किसी भी तरह की उपज बेचने के लिए विपणन स्वतंत्रता प्रदान करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसान अब अपनी उपज दूसरे राज्यों में भी बेहतर दामों पर बेच सकेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने की आशंकाओं को भी दरकिनार करते हुए कहा कि यूपीए शासन काल की तुलना में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। श्री गंगवार ने श्रमिकों से सम्बंधित प्रमुख श्रम कानूनों के लाभों के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की और बाद में भारतीय मज़दूर संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में भी इस बारे में बातचीत की।

उद्योग और कामगार एक दूसरे के पूरक हैं और इसलिए सभी को बदलते समय के साथ मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि इन सुधारों से आने वाले दिनों में श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। श्री गंगवार ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों श्रम संहिताओं को अपनी सहमति दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभूतपूर्व श्रम कल्याण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के अलावा इन श्रम संहिताओं से व्यापार को आसानी से आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उद्योग और कामगार एक दूसरे के पूरक हैं और इसलिए सभी को बदलते समय के साथ मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने देश के अग्रणी उद्योगपतियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के अंतिम लक्ष्य को हासिल करने के लिए आर्थिक प्रगति के लिए सरकार को सहायता प्रदान करें। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ कामकाजी स्थिति में भी सुधार लाने से वृद्धि और विस्तार में बढ़ोतरी होती है।

श्री गंगवार ने सार्वभौमिक और अनिवार्य स्तर की मजदूरी, महिला कामगारों के लिए समान मजदूरी तथा काम करने के अवसर, नियुक्ति पत्र जारी करने, देश के विशाल कार्यबल के लिए ईपीएफ और ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को बढ़ावा, जीआईजी मंच की उपलब्धि और बागान श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने आदि प्रावधानों का उल्लेख किया।

केंद्रीय मंत्री ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि, नौकरियां खोने वालों के लिए पुनः कौशल निधि, प्रवासी श्रमिकों की व्यापक परिभाषा और बेहतर लक्ष्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनके डेटा संग्रह आदि प्रावधानों के लाभों के बारे में विस्तार से बताया। श्री गंगवार ने इस बात पर जोर दिया कि ये सुधार तरक्की के नए रास्ते लाने वाले और परिवर्तनकारी हैं क्योंकि कुछ पुराने कानून पिछले 73 वर्षों से अस्तित्व में हैं और ये सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले एक पंजीकरण, एक लाइसेंस, एक रिटर्न के स्थान पर रिटर्न की एक नई व्यवस्था करके कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन कानूनों को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

श्री गंगवार ने असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना जैसे पहले से किए गए उपायों का हवाला देते हुए कामगारों के कल्याण के लिए वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, ईपीएफ और ईएसआईसी सेवाओं की पोर्टेबिलिटी और विस्तार हो रहा है और महिलाओं को खानों में काम करने का अधिकार देना जैसे कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि मजदूरी पर संहिता के अलावा पिछले साल तीन प्रमुख श्रम कानूनों को अधिनियमित किया गया था। सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों पर संहिता को संसद द्वारा पारित किया गया और हाल ही में अधिनियमित किया गया है। ■

संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थाओं में बदलाव आज समय की मांग है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 सितम्बर, 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव, आज समय की मांग है। श्री मोदी ने कहा कि जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं, जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन का पूरा पाठः

संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर मैं भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की तरफ से प्रत्येक सदस्य देश को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी के सामने भारत के 130 करोड़ लोगों की भावनाएं इस वैश्विक मंच पर साझा करने आया हूं।

1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहौल, साधन-संसाधन, समस्याएं-समाधान सब कुछ भिन्न थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ वो भी उस समय के हिसाब से ही था। आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की, आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और हैं। इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? सदी बदल जाये और हम न बदलें तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है।

अगर हम बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं। लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेक युद्ध हुए, अनेक गृहयुद्ध भी हुए। कितने ही आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को थर्राकर रख दिया, खून की नदियां बहती रहीं।

इन युद्धों में, इन हमलों में, जो मारे गए, वो हमारी-आपकी तरह इंसान ही थे। वो लाखों मासूम बच्चे जिन्हें दुनिया पर छा जाना था, वो दुनिया छोड़कर चले गए। कितने ही लोगों को अपने जीवन भर की पूंजी गंवानी पड़ी, अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा। उस समय और आज भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास क्या पर्याप्त थे? पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है, एक प्रभावशाली रिस्पांस कहां है?

संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव,

स्वरूप में बदलाव, आज समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र का भारत में जो सम्मान है, भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के सुधार को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या यह प्रक्रिया कभी एक निर्णायक अंत तक पहुंच पाएगी।

आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की व्यवस्था से अलग रखा जाएगा? एक ऐसा देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश, जहां विश्व की 18 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश, जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक विचारधाराएं हैं, जिस देश ने सैकड़ों वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और सैकड़ों वर्षों की गुलामी, दोनों को जीया है। जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं, जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने।

जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? संयुक्त राष्ट्र जिन आदर्शों के साथ स्थापित हुआ था और भारत की मूल दार्शनिक सोच बहुत मिलती-जुलती है, अलग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के इसी हॉल में ये शब्द अनेक बार गूंजा है- वसुधैव कुटुम्बकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है।

संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना के लिए लगभग 50 शांति मिशन में अपने जांबाज सैनिक भेजे। भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना में सबसे ज्यादा अपने वीर सैनिकों को खोया है। आज प्रत्येक भारतवासी संयुक्त राष्ट्र में अपने योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में अपनी व्यापक भूमिका भी देख रहा है।

2 अक्टूबर को 'अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' और 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस', इनकी पहल भारत ने ही की थी। आपदा निरोधी संरचना गठबंधन और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ये भारत के ही प्रयास हैं। भारत ने हमेशा पूरी मानव जाति के हित के बारे में सोचा है, न कि अपने निहित स्वार्थों के बारे में। भारत की नीतियां हमेशा से इसी दर्शन से प्रेरित रही हैं।

भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति से लेकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी तक, 'क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और प्रगति' की सोच हो या फिर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति हमारे विचार, सभी में इस दर्शन की झलक दिखाई देती है। भारत की भागीदारी का मार्गदर्शन भी यही सिद्धांत तय करता है। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो वो किसी तीसरे के खिलाफ नहीं होती। भारत जब विकास की साझेदारी मजबूत करता है, तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती। हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभव साझा करने में कभी पीछे नहीं रहते।

वैश्विक महामारी के बाद बनी परिस्थितियों के बाद हम 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक Force Multiplier (शक्ति वर्धक) होगा। भारत में आज यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे।

वैश्विक महामारी के इस मुश्किल समय में भी भारत के दवा उद्योग ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजीं हैं। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत का वैक्सीन उत्पादन और वैक्सीन वितरण क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। हम भारत में और अपने पड़ोस में फेज 3 क्लीनिकल ट्रायल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वैक्सीन के वितरण के लिए कोल्ड चेन और भंडारण जैसी क्षमता बढ़ाने में भी भारत सभी की मदद करेगा।

अगले वर्ष जनवरी से भारत सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के तौर पर भी अपना दायित्व निभाएगा। दुनिया के अनेक देशों ने भारत पर जो विश्वास जताया है, मैं उसके लिए सभी साथी देशों का आभार प्रकट करता हूं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उपयोग करेंगे।

हमारा मार्ग जन-कल्याण से जग-कल्याण का है। भारत की आवाज़ हमेशा शांति, सुरक्षा, और समृद्धि के लिए उठेगी। भारत की आवाज़ मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन- आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, हवाला के खिलाफ उठेगी। भारत की सांस्कृतिक धरोहर, संस्कार, हजारों वर्षों के अनुभव, हमेशा विकासशील देशों को ताकत देंगे। भारत के अनुभव, भारत की उतार-चढ़ाव से भरी विकास यात्रा, विश्व कल्याण के मार्ग को मजबूत करेगी।

बीते कुछ वर्षों में 'रिफॉर्म-परफॉर्म-ट्रांसफॉर्म' इस मंत्र के साथ भारत ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में बड़े बदलाव लाने का काम किया है। ये अनुभव विश्व के बहुत से देशों के लिए उतने ही उपयोगी हैं, जितने हमारे लिए। सिर्फ 4-5 साल में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। सिर्फ 4-5 साल में 60 करोड़ लोगों को खुले में शौच से मुक्त करना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया।

सिर्फ 2-3 साल में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा से जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने यह करके दिखाया। आज भारत 'डिजिटल लेनदेन' के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। आज भारत अपने करोड़ों नागरिकों को डिजिटल पहुंच देकर सशक्तिकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है। आज भारत वर्ष 2025 तक अपने प्रत्येक नागरिक को टी.बी. से मुक्त करने लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। आज भारत अपने गांवों के 15 करोड़ घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का अभियान चला रहा है। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने की बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की है।

वैश्विक महामारी के बाद बनी परिस्थितियों के बाद हम 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक Force Multiplier (शक्ति वर्धक) होगा। भारत में आज यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। महिला उद्यम और नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं।

आज दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ भारत की महिलाएं ही उठा रही हैं। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है, जहां महिलाओं को 26 सप्ताह की सवेतन मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है। भारत में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए भी कानूनी सुधार किए गए हैं।

भारत विश्व से सीखते हुए विश्व को अपने अनुभव बांटते हुए आगे बढ़ना चाहता है। मुझे विश्वास है कि अपने 75वें वर्ष में संयुक्त राष्ट्र और सभी सदस्य देश इस महान संस्था की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए और प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में संतुलन और संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण विश्व कल्याण के लिए उतना ही अनिवार्य है। आइए, संयुक्त राष्ट्र के 75वें वर्ष पर हम सब मिलकर अपने आपको विश्व कल्याण के लिए एक बार फिर समर्पित करने का प्रण लें। ■

समग्र नदियों की स्वच्छता पर केंद्रित है यह मिशनः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 सितम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'नमामि गंगे' मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में 6 बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने गंगा नदी पर अपनी तरह के पहले संग्रहालय 'गंगा अवलोकन' का भी हरिद्वार में उद्घाटन किया। उन्होंने एक पुस्तक रोइंग डाउंन गंगेस और जल जीवन मिशन का नया लोगो भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और जल समितियों के लिए उपयोगी 'मार्गदर्शिका' भी जारी की।

इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध करवाना है। श्री मोदी ने कहा कि नया लोगो पानी के महत्व को समझते हुए एक-एक बूंद के जल संरक्षण के लिए प्रेरित करेगा।

मार्गदर्शिका को उल्लेखित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ग्राम पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ सरकारी मशीनरी के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। रोइंग डाउन गंगेस पुस्तक के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह गंगा नदी को हमारी संस्कृति, विश्वास और धरोहर की गौरवशाली प्रतीक के रूप में स्थापित करती है।

श्री मोदी ने गंगा नदी को स्वच्छ रखने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह अपने उद्गम स्थल उत्तराखंड से लेकर अपने आखिरी पड़ाव पश्चिम बंगाल तक देश की लगभग 50% आबादी के जीवन में अहम भूमिका अदा करती है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन नदियों के संरक्षण का सबसे बड़ा मिशन है और इसका उद्देश्य सिर्फ गंगा नदी की स्वच्छता नहीं है, बल्कि यह समग्र नदियों की स्वच्छता पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नई सोच के चलते बड़ा परिवर्तन आया है और गंगा नदी जीवंत हो उठी है। अगर हमने इसके लिए पुराने तरीकों को अपनाया होता तो स्थितियां आज पुराने समय की तरह ही खराब होती, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में जनता की भागीदारी का अभाव था। श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 4 रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रही हैः

- पहला है- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बड़ी संख्या में स्थापना, जो गंगा नदी में जाने वाले दूषित जल एवं मल को शुद्ध कर सके।
- दूसरा है- इन संयंत्रों का निर्माण आगामी 10-15 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना।
- तीसरा है- गंगा नदी के पास वाले 5000 गांवों और 100 शहरों/कस्बों को खुले में शौच से मुक्त करना।
- चौथा है- गंगा की सभी सहायक नदियों में आने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए समग्रता में प्रयास किया जाना।

नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं या तो पूर्ण हो चुकी हैं या प्रगति पर हैं। इन्हीं परियोजनाओं में उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल हैं। जहां बीते 6 वर्षों में उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 4 गुना बढ़ी है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रेखांकित किया कि नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं या तो पूर्ण हो चुकी हैं या प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं परियोजनाओं में उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल हैं। जहां बीते 6 वर्षों में उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 4 गुना बढ़ी है।

प्रधानमंत्री ने उन प्रयासों का भी जिक्र किया है जिनके चलते उत्तराखंड में गंगा नदी में आने वाले 130 नालों को बंद किया गया। उन्होंने विशेष रूप से चंद्रेश्वर नगर नाले का जिक्र किया जो ऋषिकेश में मुनी की रेती पर आने वाले श्रद्धालुओं, नौकायन का आनंद लेने के लिए आने वालों की आंखों में चुभता था। उन्होंने इस नाले को बंद करने और मुनी की रेती में 4 मंजिला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए राज्य सरकार की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसा प्रयागराज कुंभ में श्रद्धालुओं ने

स्वच्छ गंगा का अनुभव किया, हमारा प्रयास है कि उसी तरह उत्तराखंड में भी हरिद्वार के कुंभ में आने वाले श्रद्धालु अविरल और निर्मल गंगा नदी का दर्शन करें। श्री मोदी ने गंगा नदी के तटों पर सैकड़ों घाटों के सौंदर्यीकरण का उल्लेख किया और हरिद्वार में एक आधुनिक रिवरफ्रंट के विकास का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा अवलोकन संग्रहालय श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा और गंगा से जुड़ी विरासत को समझने में, उसे जोड़ने में मदद करेगा। श्री मोदी ने कहा कि 'नमामि गंगे' मिशन का उद्देश्य गंगा नदी की स्वच्छता के साथ-साथ समूचे गंगीय बेल्ट के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का विकास भी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जैविक खेती और आयुर्वेदिक खेती के लिए एक समग्र योजना तैयार की है।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना से मिशन डॉल्फिन को भी मजबूती मिलेगी। जिसकी घोषणा इस साल 15 अगस्त को की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देश के 15 करोड़ घर ऐसे हैं जहां पाइप से पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

श्री मोदी ने कहा कि इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, ताकि पानी से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह मंत्रालय इस समय देश के प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराने के मिशन में लगा हुआ है।

इस समय जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 1 लाख घरों को पाइप के द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मात्र 1 वर्ष में देश के दो करोड़ परिवारों को पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने पिछले चार-पांच महीनों में कोरोना वायरस के दौरान भी 50,000 परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार की भी प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के कार्यक्रमों से अलग जल जीवन मिशन नीचे से ऊपर की ओर काम करता है, जहां उपभोक्ता और जल समितियां पूरी परियोजना की परिकल्पना करती हैं इसमें योजना के क्रियान्वयन, रखरखाव और परिचालन तक शामिल है। उन्होंने कहा कि इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि समितियों में 50% सदस्य महिलाएं हों। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सही फैसले करने में जल समितियों और ग्राम पंचायतों की मदद करने के लिए ही आज मार्गदर्शिका जारी की गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल 2 अक्टूबर को 100 दिवसीय विशेष अभियान आरंभ किया जा रहा है जिसके अंतर्गत इन 100 दिनों में देश के प्रति स्कूल और आंगनवाड़ी को पेयजल कनेक्शन सुनिश्चित किए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने हाल ही में किसानों, औद्योगिक कामगारों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई बड़े सुधार किए हैं। ■

श्रद्धांजलि

भारत के पूर्व विदेश, वित्त व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह का निधन

भारत के पूर्व विदेश, वित्त व रक्षा मंत्री श्री जसवंत सिंह का 27 सितंबर को निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। 3 जनवरी, 1938 को बाड़मेर ज़िले के जसोल गांव में जन्मे श्री सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान केन्द्र सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में अमिट छाप छोड़ी, जिसमें रक्षा, वित्त एवं विदेश मंत्रालय शामिल है।

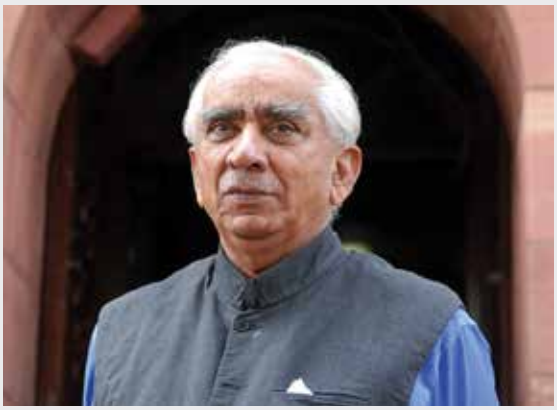

शोक संदेश

श्री जसवंत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि जसवंत सिंह जी ने पूरी लगन से हमारे देश की सेवा की, पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के जरिए। अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला और वित्त, रक्षा एवं विदेश मामलों की दुनिया में अपने श्रेष्ठ कामकाज की अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन से अत्यंत दुःखी हूं।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि श्रद्धेय अटल जी की सरकार में मंत्री रहे श्री जसवंत सिंह के निधन का समाचार दुःखद है। सरकार में विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जन-जन के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में अपना प्रत्येक क्षण समर्पित कर दिया। श्री जसवंत सिंह का जाना संगठन, समाज तथा देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके परिवार के प्रति मेरी अपार संवेदनाएं। ■

निरंतर नेतृत्व का बीसवां वर्ष

जगत प्रकाश नड्डा

भारत के राजनीतिक इतिहास में 7 अक्तूबर, 2001 की तारीखी सुबह एक मील का पत्थर है, जब श्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब से, हर बार पिछली जीत से बड़ी जीत, पिछले समर्थन से बड़ा समर्थन, लोकप्रियता का बढ़ता पायदान और अनवरत 20 वर्षों से सरकार के प्रमुख के रूप में अविजित योद्धा की तरह आगे बढ़ते श्री नरेन्द्र मोदी एक कालजयी नेतृत्व के रूप में भारतीय राजनीति में स्थापित हुए हैं। आज यानी 7 अक्तूबर, 2020 को वह एक सरकार के प्रमुख के रूप में 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा अंधेरों, अवरोधों और बाधाओं को पार करने की कहानी है, जो 'चलो जीते हैं' का सार्थक अभियान है।

हालांकि, चुनावी विजय व बड़े पैमाने पर लोकप्रियता ऐसे विषय हैं, जो अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। मगर विजय के पीछे का अथक परिश्रम और देश को आगे ले जाने का अद्वितीय संकल्प ऐसे प्रमुख तत्व हैं, जो श्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व को और निखारते हैं। यदि दृढ़-संकल्प लेने का साहसिक प्रयत्न कोई शुरू करे, तो एक संकल्प लाखों संकल्पों का उजाला बांट सकता है। इसे श्री मोदी ने पग-पग पर चरितार्थ करके दिखाया है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद की कालिमा धुल गई है और धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण और दलीय स्वार्थों के राजनीतिक विवादों पर विकासवाद की विजय हो रही है।

गुजरात के मुख्यमंत्रित्व काल से ही वह सबसे अलग थे। ऐसे समय में, जब बिजली सुधारों का मतलब राजनीतिक आत्महत्या था, उन्होंने किसानों को विश्वास में लेते हुए राज्य में बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया। वह बिजली को गुजरात के हर गांव में ले गए और इसे सरप्लस बिजली वाला राज्य बना दिया। इसी तरह, जब राष्ट्रीय स्तर के निवेशक शिखर सम्मेलन भी कभी-कभार होते थे, तब उन्होंने 2003 में 'वाइब्रेंट गुजरात' निवेशक शिखर सम्मेलन शुरू किया। तब से, यह सम्मेलन और गुजरात, दोनों एक-दूसरे के पर्याय बन गए हैं और दोनों विश्व स्तर पर निवेशकों के बीच प्रसिद्ध हो गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में तो उन्होंने रिकॉर्ड एफडीआई प्रवाह को

सुनिश्चित किया है।

विकास के प्रसिद्ध 'गुजरात मॉडल' को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे में तेजी से वृद्धि के बावजूद राज्य ने कृषि क्षेत्र में व्यापक वृद्धि देखी। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में दशकों बाद किसानों की आजादी सुनिश्चित करते हुए उनका सशक्तकरण किया और उनकी आय को दोगुना करने के लिए कई योजनाओं को क्रियान्वित किया। उनके नेतृत्व में देश के बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार दिखा है और यह और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने बालिकाओं को बचाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की, जिसका समाज में सार्थक प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि, यह बालिका शिक्षा के लिए गुजरात में उनके द्वारा शुरू की गई 'कन्या केलवानी' कार्यक्रम का एक तार्किक विस्तार था, जहां राज्य सरकार गांवों में जाकर लड़कियों के स्कूल में नामांकन को प्रोत्साहित किया करती थी।

एक निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी के लंबे और अजेय कार्यकाल का कारण उनकी खुद को लगातार चुनौती देने की क्षमता है, जो किसी भी बाहरी चुनौतीकर्ता की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और आक्रामक है। वह दुर्लभ लक्ष्यों को निर्धारित करने का जोखिम लेने से भी नहीं हिचकते। उन्होंने अपनी प्रत्येक प्रमुख योजना के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए, चाहे वह स्वच्छता अभियान हो, ग्रामीण विद्युतीकरण हो, सबके लिए आवास हो, आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि हो, हर घर तक पीने योग्य पानी पहुंचाना हो या किसानों की आय को दोगुना करना हो। आज विकास की योजनाएं, नीतियां, सिद्धांत, लाभांश और संकल्प सही परिणामों के साथ सही लोगों तक पहुंच रहे हैं। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, अनुच्छेद 370 का उन्मूलन हो या एक साथ तीन तलाक का खात्मा, श्री नरेन्द्र मोदी ने दिखा दिया है कि इच्छाशक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे देश की दशा-दिशा बदल सकती है। वह भारत व भारतीयों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को उत्साहित करते हैं और उनमें से सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाने का रास्ता बताते हैं। उन्होंने स्वच्छता अभियान को जन-जन का आंदोलन बना दिया। एक ऐसे राष्ट्र में, जहां प्रचलित राजनीतिक संस्कृति अधिक से अधिक सब्सिडी देने के

शेष भाग पृष्ठ 30 पर...

कांग्रेस को है बिचौलियों की चिंता, इसलिए किसानों को कर रही गुमराह

राकेश सिंह

कृषि सुधार कानून में कुछ भी किसानों के विरोध में नहीं है। देश का किसान पूरी तरह से इस कानून के साथ है। लेकिन कुछ राजनैतिक दल किसानों के नाम पर आंदोलनरत हैं, हालांकि यह ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। देश का अन्नदाता जागरूक है और अपना अच्छा-बुरा समझता है। उसने समझ लिया है कि यह कानून उसके अधिकारों की रक्षा करता है और उसे समृद्धि की दिशा में आगे ले जायेगा।

वर्ष, 2011 में कांग्रेस सत्ता में थी, जब सदन में कृषि सुधार पर बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिब्बल ने जो कहा था, "जब किसान बोता है और उसे बेचना चाहता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है। उसे मालूम नहीं है किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो पैतीस से चालीस फीसदी सामान खराब हो जाता है। इस बीच आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं। बेचारे किसान का जो सामान बिकता है, उसका 15-17 फीसदी ही उसे मिलता है। बाकी बिचौलियों को चला जाता है। विपक्षी दलों को तय करना है कि वे किसान के साथ हैं या बिचौलियों के साथ।"

यह बयान कपिल सिब्बल का है। वे उस समय कृषि सुधारों पर बोलते हुए विपक्ष से पूछ रहे थे कि वे किसके साथ हैं। यही सवाल आज उनकी पार्टी से पूछा जा रहा है कि वे किसान के साथ हैं या बिचौलियों के साथ।

जाहिर है कांग्रेस बिचौलियों के साथ है। अगर वह किसानों के साथ होती तो हंगामा नहीं करती। सड़क से संसद तक कृषि कानून का समर्थन करती। लेकिन वह तो विरोध का बिगुल बजा रही है और बिचौलियों के लिए काम कर रही है। यह उसका स्वभाव भी रहा है। बिचौलिए हमेशा उसके प्रिय रहे हैं। फिर चाहें बात खेती-बाड़ी की हो या किसी और क्षेत्र की। इनका तो वास्ता ही इन्हीं से रहा है। तभी तो वह किसानों को गुमराह कर रही है। नहीं तो जो विधयेक उनके लिए है, उसे सदन से पास कराती। लेकिन वह तो विरोध पर उतर आई है। विरोध ऐसा कि उप सभापति पर हमला कर दिया जाता है, जो संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मगर जिसे बिचौलियों की चिंता हो, उसके लिए संसदीय मर्यादा कहां मायने रखती। रही बात कृषि सुधार की तो कांग्रेस का घोषणा पत्र, उसके दोहरे चरित्र का गवाह है। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, वही कृषि सुधार कानून कह रहा है। वही कानून जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। देशव्यापी आंदोलन चला रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रही है। किसानों को बता रही है कि यह कानून किसान विरोधी है। जाहिर है वह किसानों की हितैषी नहीं है। अन्नदाता को ऐसे दलों के बहकावे से बचना चाहिए। उन्हें समझना होगा कि सरकार कृषि सुधार के लिए जो तीन कानून लेकर आई है, वह उनके हित में हैं। इससे जहां किसानों की आय दोगुना होगी वहीं बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। किसान अपना उत्पाद देश के किसी कोने में बेच सकेगा। 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना बढ़ाकर 60 अरब डालर करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति की मूल भावना इसी में समाहित है। किसानों की आय दोगुनी हो, किसान समृद्ध हो और साहूकारी के मकड़जाल से बाहर निकल सके।

इससे किसान को अब बिचौलियों की चौखट पर सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। यह कृषि सुधार विधेयक किसान के आत्मसम्मान की भी रक्षा करता है।

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नए कृषि सुधारों से किसानों की जमीन भेंट चढ़ जाएगी। पूंजीपतियों का आधिपत्य हो जाएगा और किसान मात्र मजदूर बनकर रह जाएगा, परन्तु ऐसा है ही नहीं। बल्कि इस कानून में सारे अधिकार किसानों के ही पास है। साथ ही अधिनियमों में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि किसान के हित सुरक्षित रहें। कृषि सुधार कानून मोदी जी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की एक उदारवादी नीति है। इससे किसान को अब बिचौलियों की चौखट पर सिर नहीं झुकाना पड़ेगा।

यह कृषि सुधार विधेयक किसान के आत्मसम्मान की भी रक्षा करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 52 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हैं। यानी कि भारत की आधी जनसंख्या कृषक है। बावजूद इसके जीडीपी में कृषि का योगदान 17-18 प्रतिशत मात्र है। किसान को अब तक एक किलो का दाम लगभग 20 रुपए मिलता है और बाजार में जाते-जाते इसकी कीमत 65-100 रुपए हो जाती है। बीच के पैसे कहां गए, उसी को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। आवश्यक अधिनियम के अन्तर्गत किसान अब प्याज, दालें, आलू एवं अन्य चीजों का भंडारण कर सकता है।

यह कानून किसान को अधिकार देता है कि वह किसी भी कंपनी से सीधे अनुबंध कर सकता है। इसका लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। हमारे देश में लगभग 78 फीसदी ऐसे किसान हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जोत है। उनको नई

तकनीकी देना कम्पनियों की जिम्मेदारी होगी। नई तकनीक के जरिए किसान अपनी खेती को ज्यादा उपजाऊ बना पाएगा। वर्तमान सरकार का यह एक ऐतिहासिक कदम है। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में यह कानून कारगर साबित होगा। किसान को किसानी छोड़कर पलायन नहीं करना होगा।

वर्तमान सरकार के इस कदम से यह साबित हो रहा है कि देश का किसान भगवान है और वह पुनः नायक बनेगा, जिसके बल पर हमारा देश 'सोने की चिड़िया' बोला जाता था। 1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रड्यूट्सन मार्केटिंग एक्ट लाने के बाद कृषि विपणन समितियां बनी थीं। इन समितियों का उद्देश्य बाज़ार की अनिश्चितताओं से किसानों को बचाना था। किन्तु केंद्रीय स्तर पर आने के बावजूद इसका मकसद पूरा नहीं हो पाया। मंडी ढांचे में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन इसका प्रभाव सीधे किसानों पर पड़ा। दूसरी ओर इनके आधुनिकीकरण करने और प्रतिस्पर्धी माहौल गढ़ने की भी कोई कोशिश नहीं हुई।

समय बीतने के साथ कई राज्यों ने एपीएमसी मंडियों में शुल्क को हद से ज्यादा बढ़ा दिया। जैसे मंडियों में ग्रामीण विकास निधि, कृषि कल्याण उपकर, विकास उपकर लगा दिए गए। इसी तरह कुछ मंडियों में फलों एवं सब्जियों के कमीशन एजेंटों पर 4-8 फीसदी शुल्क लगा दिए गए। इस समय पंजाब में मंडी कर 6.5 और 2.5 फीसदी आढ़ती चार्ज है। इसके अलावा कई तरह के सेस है। कुल मिलाकर 14.5 फीसदी का चार्ज किसानों को सहन करना पड़ता है। वहीं हरियाणा में यह 11.5 फीसदी है। एक तरह जहां किसान अपनी फसल को बचाने की गुहार लगाता रहता है, वहीं किसान के सिर पर इन भारी करों का बोझ भी होता है। कृषि सुधार कानून सराहनीय इसलिए भी है, क्योंकि किसान को इन करों के बोझ तले अब दबना नहीं होगा।

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद कहते हैं- यह कानून देखा जाए तो सभी मंडी व्यापारियों या आढ़तियों के संघ जैसा बन गया है। इस वजह से किसानों को अपना उत्पाद सीधे किसी को भी बेचने की छूट होगी। इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेगें। अब कानूनी रूप से मान्य बिचौलियों के न होने से किसान सीधे अपना उत्पाद बेच सकेंगे। जहां तक बात अनुबंध कृषि की है तो वह नई नहीं है। देश के तमाम राज्यों में की जा रही है।

देश के कई राज्यों के किसानों ने अनुबंध कृषि द्वारा अपनी किस्मत चमकाई है। जिस पंजाब में इन दिनों किसान आंदोलनरत हैं, उसी राज्य के (मोगा जनपद स्थित गांव इन्द्र गढ़) किसान मजिंदर सिंह हैं। उनके पास 20 एकड़ ज़मीन थी, फिर भी वे कर्ज में डूबे रहते थे। 2005 में जब खेती से निराशा होने लगी, तब उन्होंने खेती छोड़ने का फैसला किया। तभी उनके किसी मित्र ने कृषि अनुबंध की जानकारी दी। उन्होंने अपनी ज़मीन का अनुबंध एक कंपनी से किया और सफलता की नई इबारत लिखी।

आज वे 100 एकड़ जमीन के स्वामी बन चुके हैं। सामान्य किसान जहां प्रति एकड़ चालीस से पचास हजार रुपए कमाता है। वहीं मंजदिर सिंह 1.50 लाख रुपए कमा रहे हैं और किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। किसान अपना हित और अहित अच्छी तरह समझता है। सचाई यह है कि इस कानून में कुछ भी किसानों के विरोध में नहीं है। ■

(लेखक लोकसभा सांसद हैं)

पृष्ठ 28 का शेष...

बारे में थी, उन्होंने लोगों को अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित किया, ताकि गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल सके।

वह एक गुजराती हैं, पर उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह किसी भी जाति, समुदाय, वर्ग या क्षेत्रीय विचारों के लिए पक्षपात नहीं करते। उनकी अपील इन अलगावों से कहीं ऊपर है, जो देश में लोगों को सिर्फ एक उद्देश्य के लिए एकजुट करती है, और वह है भारत की एकता, श्रेष्ठता व महानता।

भारत की सर्वश्रेष्ठ परंपरा नफरत को प्यार के स्पर्श से जीतने का भाव पैदा करती है। यह आपदा के समय एकजुट होकर एक-दूसरे के लिए जीना सिखाती है। हमारी परंपरा बताती है कि सत्य द्वारा संचालित इस तरह के मौन, दृढ़ व गरिमापूर्ण संकल्प सभी प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करते हैं। ये सभी प्रधानमंत्री श्री मोदी के व्यक्तित्व में समाहित हैं, जो उनकी नीति 'सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास' में झलकता है। दो दशकों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जी-तोड़ कोशिशें की गईं। यहां तक कि एक छोटे से अविश्वास का मतलब उनकी राजनीतिक यात्रा का अंत भी था।

अक्सर, जो 'बड़े छवि' वाले लोग होते हैं, वे दूरदर्शी होते हैं, लेकिन वे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने विजन को क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। फिर, कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में तो अच्छे हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर को समझ नहीं पाते हैं। पर श्री मोदी ने दूरदर्शिता, संकल्प को प्राप्त करने की सिद्धि और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन, तीनों को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर लिया है। जब वह एक सरकार के प्रमुख के रूप में अपने 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब उनकी पिछली उपलब्धियों के आधार पर उनका आकलन पहले से ही हो रहा होगा, लेकिन उनका सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है और वह होगा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के रूप में। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

केरल में मेगा फूड पार्क का शुभारंभ

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए केरल के पलक्कड़ जिले में राज्य के पहले व देश के बीसवें मेगा फूड पार्क (किन्फ्रा मेगा फूड पार्क) का शुभारंभ 1 अक्टूबर को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनरायी विजयन ने किया। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे।

श्री तोमर ने कहा कि यह पार्क केरल में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें 25-30 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आएगा और अंततः साल भर में 450-500 करोड़ रु. का कारोबार होगा। यह पार्क 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करेगा और 25,000 से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करेगा। इससे फल-सब्जियों व अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। पार्क में खाद्य प्रसंस्करण की आधुनिक अवसंरचना से केरल व आसपास के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी, उत्पादकों, प्रोसेसर व उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार, देश को लचीली खाद्य अर्थव्यवस्था और विश्व का खाद्य कारखाना बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को 'आत्मनिर्भर भारत' का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाया है। देश में बीस मेगा फूड पार्क केंद्र के सहयोग से खुल चुके हैं, सत्रह अन्य प्रोजेक्ट भी मंजूर कर दिए गए हैं, जिनमें केरल के अलेप्पी जिले में भी एक पार्क का अनुमोदन किया गया है। श्री तोमर ने कहा कि देश के किसानों पर गर्व है, जिनकी कड़ी मेहनत से देश में खाद्यान्न का भंडार भरा हुआ है। देशवासियों की जरूरत तो पूरी हो ही रही है, खाद्यान्न सरप्लस है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कृषि क्षेत्र की गैप्स को लगातार भरने में जुटे हैं, इसीलिए एक लाख करोड़ रु. के एग्री इंफ्रा फंड की शुरुआत की गई है, वहीं बजट की घोषणानुसार किसान रेल प्रारंभ हो चुकी है। कृषि सुधारों से निजी निवेश गांव-गांव तक पहुंचेगा, जिससे कृषि उद्यमिता काफी बढ़ेगी व किसानों को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि मूल्यवर्धित वस्तुओं के निर्यात में ज्यादा संभावनाएं है, जिससे न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, बल्कि घरेलू बाजार में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। भारत सरकार कृषि क्षेत्र के कायाकल्प पर काम कर रही है। वित्त आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने राज्यों का फंड भी बढ़ाया है। केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम पीएम किसान संपदा योजना से भी किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। साथ ही, आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में केंद्र ने नई स्कीम- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) शुरू की है।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि पार्क में सृजित सुविधाओं से कृषि उपज की बर्बादी कम होगी, बल्कि मूल्यवर्धन भी सुनिश्चित होगा। इससे किसानों की उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। यह किसानों, स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म उद्यमियों को प्रोसेसिंग के अवसर उपलब्ध कराएगा और आसपास के क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करेगा। ■

किन्फ्रा मेगा फूड पार्क

यह परियोजना 79.42 एकड़ भूमि पर 102.13 करोड़ रु. की लागत से प्रारंभ हुई है। यहां केंद्रीय प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निर्मित सुविधाओं में किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं को मल्टी उत्पाद कोल्ड स्टोरेज, शुष्क माल गोदाम, पैक हाउस (छंटाई, श्रेणीकरण, पैकिंग), पक्वन चैम्बर्स, मसाला शुष्कीकरण एवं प्रसंस्करण सुविधा, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भी शामिल हैं।

किसानों को लाभान्वित करने के लिए खेतों के पास प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए पैक हाउस की सुविधा के साथ एर्नाकुलम (मझावनूर), त्रिशूर (कोराट्टी), मलप्पुरम (कक्कंचरी) और वायनाड (कलपेट्टा) जिलों में 4 प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (पीपीसी) की स्थापना भी की गई है। इस मेगा फूड पार्क से पलक्कड़ जिले के साथ-साथ मलप्पुरम जिले के आसपास और केरल के त्रिशूर व तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के लोगों को भी फायदा होगा।

बिहार विधानसभा चुनाव 2020

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और महागठबंधन के बीच है। राजग में जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल (यूनाइटेड), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल हैं, वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वामदल। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) अलग से चुनाव मैदान में हैं।

विदित हो कि निर्वाचन आयोग ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए तीन चरणों में करवाने की घोषणा की है। मतदान 28 अक्तूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। 28 अक्तूबर को पहले चरण में 16 ज़िलों की 71 सीटों पर मतदान होगा। 3 नवंबर को दूसरे चरण में 17 ज़िलों की 94 सीटों पर मतदान होगा। 7 नवंबर को तीसरे चरण में 15 ज़िलों की 78 सीटों पर मतदान होगा। कोरोना काल में यह सबसे बड़ा और पहला चुनाव होगा।

बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) 122 और भाजपा 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 06 अक्टूबर को भाजपा और जदयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की गई।

इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों का एनडीए गठबंधन है और सीटों के बंटवारे का निर्णय हो चुका है। न्याय के साथ विकास और समाज के हर तबके का उत्थान हमलोगों का मकसद है। समाज में प्रेम और भाइचारे का भाव होना चाहिए। बिहार को हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सीट और कैंडिडेट तय हो चुके हैं। जदयू और भाजपा साथ चुनाव लड़ेंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2006 से हमलोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक साथ काम करने का लंबा अनुभव है। हमलोगों का 15वां साल है। इससे पहले जिन लोगों ने काम किया था उस समय बिहार की क्या स्थिति थी, सभी के सामने है। कितने दंगे होते थे सभी को मालूम है। कहीं सड़क नहीं थी। बिजली का क्या हाल था। स्कूल नहीं चल रहे थे। कॉलेज के शिक्षकों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती थी। उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। विपक्ष को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो बिजली, पानी, सड़क और प्रवासियों को मुद्दा बनायें। हमने एक-एक मुद्दे का प्रभावी तरीके से समाधान का प्रयास किया है। हम तीन चौथाई के बहुमत के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनायेंगे। भाजपा ने अपने कोटे से वीआईपी को विधानसभा की 11 सीटें दी हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय महासचिव एवं भाजपा बिहार प्रदेश प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव, भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी श्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल, बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ■

देवेन्द्र फडणवीस बने भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 30 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस को बिहार विधानसभा चुनाव हेतु चुनाव प्रभारी नियुक्त किया।

जहां कहीं भी आत्मा है, वहीं एक कहानी है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितम्बर को 'मन की बात 2.0' की 16वीं कड़ी में किस्सा-गोई के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने उल्लेख किया कि कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता और कहा, 'जहां कहीं भी आत्मा है, वहीं एक कहानी है।' श्री मोदी ने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा कहानी कहने की परंपरा के महत्व पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि उनकी यात्राओं के दौरान बच्चों के साथ उनकी परस्पर बातचीत के द्वारा उन्होंने महसूस किया कि चुटकुले व्यापक तरीके से उनके जीवन में समाहित हो गए थे और उनका कहानियों से कोई परिचय ही नहीं था।

श्री मोदी ने देश में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत ने हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा का पोषण किया है, जहां कहानियों में पशु-पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके।

उन्होंने धार्मिक कहानियां कहने की एक प्राचीन पद्धति 'कथा' का उल्लेख किया, तमिलनाडु और केरल में 'विल्लू पाट' का उदाहरण दिया जो कहानी और संगीत का एक आकर्षक सामंजस्य है और कठपुतली की जीवंत परम्परा की भी चर्चा की। श्री मोदी ने विज्ञान और विज्ञान कथाओं पर आधारित किस्सा-गोई की बढ़ती लोकप्रियता का भी उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने कहानीकारों से ऐसा तरीका खोजने का आग्रह किया जो देश की नई पीढ़ी को कहानियों के माध्यम से महापुरुषों और महान नारियों के साथ जोड़ सकें। उन्होंने कहा कि कहानी कहने की कला को अवश्य ही प्रत्येक घर में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए और बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाना सार्वजनिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए।

श्री मोदी ने विचार व्यक्त किया कि प्रत्येक सप्ताह, परिवार के सदस्यों को करुणा, संवेदनशीलता, वीरता, बलिदान, बहादुरी, आदि जैसी विषय वस्तुओं का चयन करना चाहिए और प्रत्येक सदस्य को उस विषय पर एक कहानी सुनानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश शीघ्र ही स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाने जा रहा है और कहानी सुनाने वालों से आग्रह किया कि वे अपनी कहानियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायी कहानियों को प्रसारित करें। प्रधानमंत्री ने उनसे इन कहानियों के माध्यम से नई पीढ़ी को 1857 से लेकर 1947 तक की प्रत्येक बड़ी और छोटी घटनाओं को प्रस्तुत करने को कहा।

'आत्मनिर्भर भारत' के लिए कृषि क्षेत्र की मजबूती आवश्यक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' में कहा कि कोविड संकट के दौरान देश के किसानों ने शानदार सहनशीलता का परिचय दिया है। श्री मोदी ने कहा कि यदि कृषि क्षेत्र मजबूत रहेगा, तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत रहेगी।

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में यह क्षेत्र कई प्रतिबंधों से मुक्त हुआ है और इसने कई मिथकों से भी मुक्त होने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किसान श्री कंवर चौहान का उदाहरण साझा किया, जो मंडी के बाहर अपने फलों और सब्जियों के विपणन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन 2014 में फलों और सब्जियों को एपीएमसी अधिनियम से बाहर रखा गया, जिससे उन्हें बहुत फायदा हुआ।

उन्होंने एक किसान उत्पादक संगठन का गठन किया और उनके गांव के किसान अब स्वीट कॉर्न तथा बेबी कॉर्न की खेती करते हैं और सीधे दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं एवं फाइव स्टार होटलों को आपूर्ति करते हैं, जिससे उनकी आय में काफी वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि इन किसानों को अपने फल और सब्जियां कहीं भी तथा किसी को भी बेचने की सुविधा है और यही उनकी प्रगति की नींव है। अब पूरे देश में किसानों को उनके सभी प्रकार के उपज के लिए यह सुविधा प्रदान की गयी है।

श्री मोदी ने कहा कि नवाचारों और नई तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने गुजरात के एक किसान इस्माइल भाई का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपने परिवार द्वारा हतोत्साहित करने के बावजूद खेती की। उन्होंने ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग करते हुए आलू की खेती की। उच्च गुणवत्ता वाले आलू अब उनकी पहचान बन गए हैं, जिसे वे बड़ी कंपनियों को बिचौलियों के बिना सीधे बेचते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। ■

कृषि विधेयक पर विपक्ष किसानों को कर रहा गुमराह: अरुण सिंह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह ने कहा कि कृषि विधेयक 2020 किसानों के लिए वरदान है। विपक्ष झूठ और भ्रम फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहा है। गत 3 अक्टूबर को सहारनपुर स्थित सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह ने कहा कि कृषि विधेयक 2020 लाकर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है। मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर किसान बनाना चाहती है और देश में किसानों की दशा सुधारने के लिए संकल्पित है। विपक्ष इस मामले में लगातार किसानों को गुमराह कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि यह बिल किसानों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। किसान को अपनी फसल बेचने के कई विकल्प इस बिल के माध्यम से सरकार ने दिए हैं। अब वह अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है और बिचौलिया की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं रहेगी।

श्री सिंह ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि विपक्ष कह रहा है कि इस बिल से एमएसपी खत्म कर दी जाएगी जबकि इसके बाद सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं करने जा रहा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि किसान अपनी भूमि को पूंजीपतियों को बेच दे, जबकि तथ्य यह है कि

किसानों को इन विधेयकों में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। किसानों की भूमि की बिक्री या गिरवी रखना पूर्णतः निषिद्ध है और किसानों की भूमि भी किसी भी तरह की रिकवरी से सुरक्षित है।

श्री सिंह ने कहा कि हम एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध कराएंगे, जहां किसी भी विवाद व समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में किसान तुरंत अपने स्थानीय एसडीएम के पास जाकर अपनी समस्याओं का निवारण करा सकेगा। ■

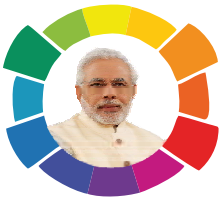

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

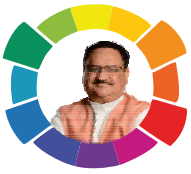

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हिमाचल प्रदेश के सिस्सू गांव में आयोजित 'आभार समारोह' में शामिल हुए। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग 'अटल सुरंग' का उद्घाटन किया

हिमाचल प्रदेश के मनाली में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग 'अटल सुरंग' को राष्ट्र को समर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, साथ में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर व अन्य

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive
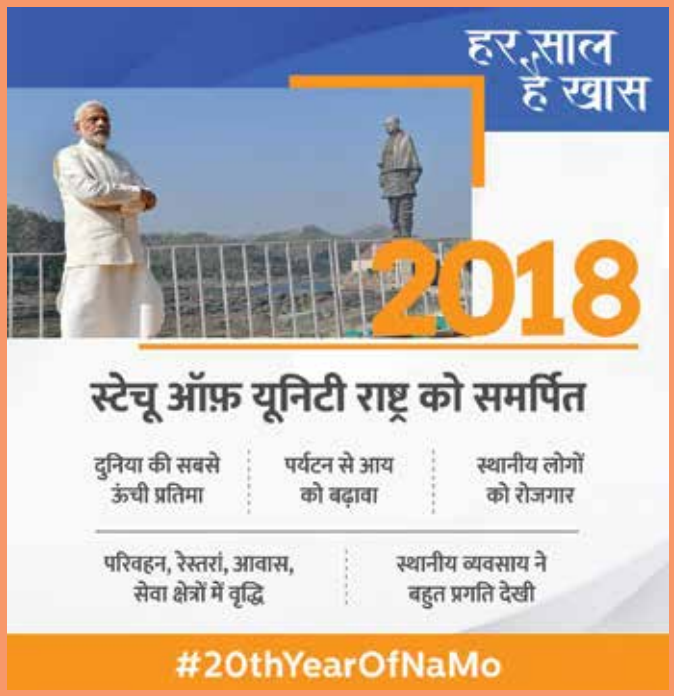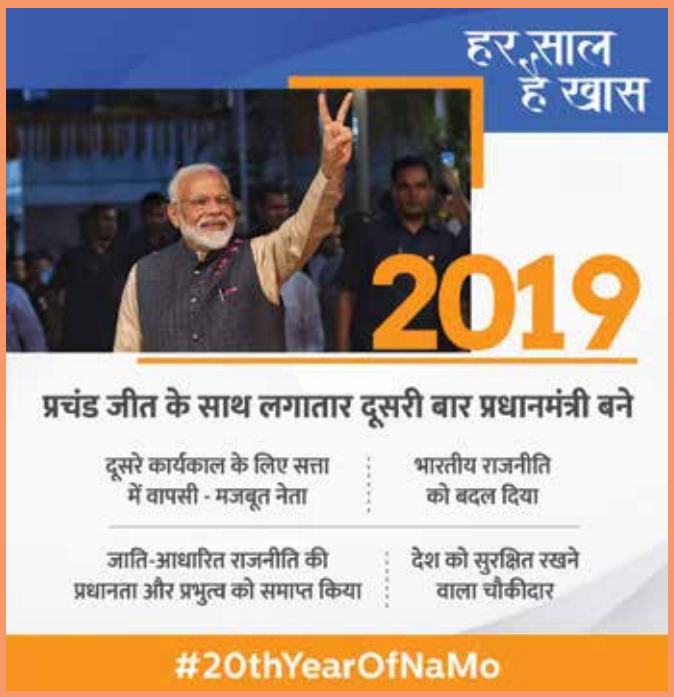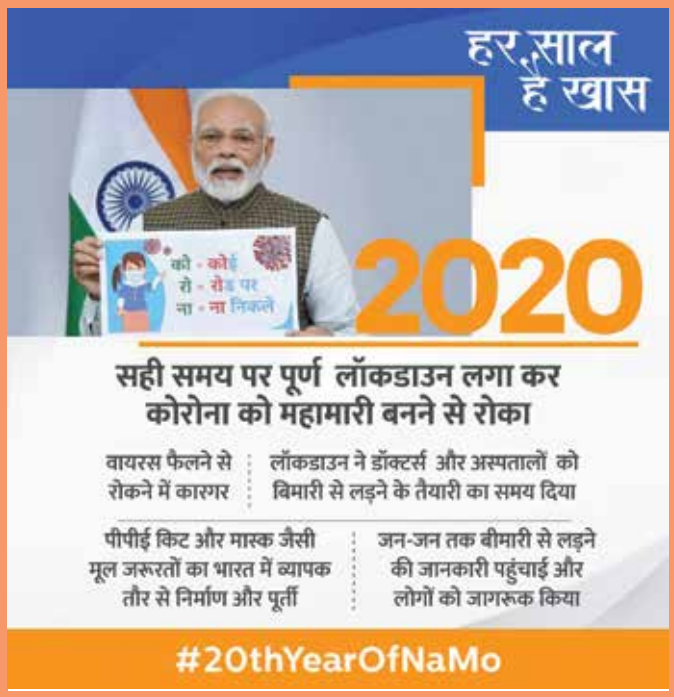
प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20